अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बुधवार, 14 फरवरी 2024

संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियां हैं, शिक्षा उनमें सबसे बढ़कर है।
- सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

चुनाव आसन्न हैं और किसान एक बार फिर दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं। हालांकि इस बार परिदृश्य अलग है। तीन साल पहले सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर आंदोलन की समाप्ति हुई थी। समूचे प्रकरण का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए।

फिर किसान, फिर दिल्ली

तीन साल पहले अपने आंदोलन के जरिये मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त कराने में कामयाब रहे किसान अब लोकसभा चुनाव से ऐन पहले एक बार फिर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर आ रहे हैं, लेकिन यह पिछले आंदोलन से कई मायनों में अलग है। इससे पहले चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों ने किसानों के साथ मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून और कर्ज की माफी जैसे मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण बात नहीं बन सकी। उल्लेखनीय है कि 2020-21 में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 500 से ज्यादा किसान संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन किया था, जिसमें लंबे संघर्ष के बाद उन्हें कामयाबी भी मिली थी। जबकि इस बार किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में 250 किसान संगठनों ने अपनी बारह सूत्री मांगें रखी हैं, जिनमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, बिजली संशोधन विधेयक-2020 को खत्म किया जाए, भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 दोबारा लागू किया जाए, अक्तूबर, 2021 में लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाले अपराधियों को कठोर सजा मिले, इत्यादि प्रमुख हैं। किसानों का यह कहना कि तीन साल पहले के आंदोलन को वापस लेते वक्त सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का जो वादा किया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है, आंदोलन के उद्देश्य को वैधता देता है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो खुले बाजार में फसलों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा देने के लिए जरूरी है, किसानों के लिए हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश में इसका सबसे ज्यादा लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिला है। इसके बावजूद इसमें कतई संदेह नहीं कि देश के अन्नदाताओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से अपनी बात

रखने का मौलिक हक है, बशर्ते उसमें, जैसा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी कहा है, कानून-व्यवस्था को नुकसान न पहुंचे, हिंसा न हो और आम जन-जीवन भी अस्त-व्यस्त न हो। चुनाव निकट है, ऐसे में आश्चर्य नहीं, कुछ राजनीतिक दल इन स्थितियों का फायदा उठाने की ताक में भी हो सकते हैं, जिससे बचा जाना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा नहीं, संवाद महत्वपूर्ण है। इसलिए, शांतिपूर्ण ढंग से समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए।

रंग गई पग-पग धन्य धरा

कहा जाता है कि वसंत में मन-प्राण खिल उठते हैं। वसंत पंचमी के दिन से ही लोग एक-दूसरे को अबीर लगाना शुरू कर देते थे। लेकिन आज सामूहिकता की वह भावना लगभग खत्म होती जा रही है। हम अपनी समृद्ध परंपरा को भूलते जा रहे हैं। परंपरा इकहरी नहीं होती, वह हमेशा समृद्ध और बहुलतावादी होती है।

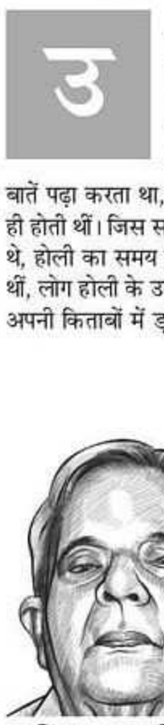

विश्वनाथ त्रिपाठी
वरिष्ठ साहित्यकार

उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर अक्सर बहुत-सी चीजें तरह-तरह से याद आती हैं। वसंत पंचमी की याद आते ही मुझे अपने छात्र जीवन की याद आती है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है-ऋतुराज वसंत। कविताओं में वसंत के बारे में अच्छी-अच्छी बातें पढ़ा करता था, लेकिन स्थिति यह थी कि परीक्षाएं भी वसंत ऋतु में ही होती थीं। जिस समय कविता में वसंत के प्रति उद्गार व्यक्त किए जाते थे, होली का समय करीब होता था, गांव की मंडलियां फाग गाया करती थीं, लोग होली के उत्सव की तैयारियां करने लगते थे, उस समय हम छात्र अपनी किताबों में डूबे होते थे। इम्तिहान के बुखार में डूबे हम छात्रों को इस उमंग-उत्साह में शामिल होने का मौका नहीं मिलता था।

परीक्षा करीब आते देख मां-बाप पढ़ाई करने के लिए हमेशा डांटते रहते थे। यह वह दौर था, जब कहा जाता था कि *पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे होगे खराब।* ऐसे में, अक्सर ईश्वर से गुहार लगाते थे कि हे भगवान, वह दिन कब आएगा, जब हमारा भी वसंत होगा! जब मैंने एमए की परीक्षा दी, तब जान में जान आई कि अब परीक्षा का कोई भय नहीं रहा, अब वसंत मनाऊंगा।

लेकिन उसी बीच छात्र जीवन में ही हमने केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता पढ़ी थी-*वसंती हवा।* वह कविता पढ़ने में इतनी अच्छी लगती थी कि वसंत के प्रति मन में एक तरह का अनुराग उत्पन्न हो गया था। *हवा हूं हवा मैं, वसंती हवा हूं* से शुरू होकर यह कविता *चढ़ी पेड़ महुआ,/थपाथप मचाया;/गिरी धम्म से फिर,/चढ़ी आम ऊपर,/उसे भी झकोरा,/किया कान में 'कू',/उतरकर भगी मैं,/हरे खेत पहुंची -/वहां, गेहुंओं में/लहर खूब मारी* से होते हुए आखिर में *मुझे देखते ही/अरहरी लजाई,/मनाया-बनाया,/न मानी, न मानी;/उसे भी न छोड़ा -/पथिक आ रहा था,/उसी पर ढकेला;/हंसी जोर से मैं,/हंसी सब दिशाएं,/हंसे लहलहाते/हरे खेत सारे,/हंसी चमचमाती/भरी धूप प्यारी;/बसंती हवा में/हंसी सृष्टि सारी!/हवा हूं, हवा मैं/बसंती हवा हूं!* पर

खत्म होती है। इस विलक्षण कविता की संरचना इतनी अनूठी है, कि इसमें गांव की एक अल्हड़ लड़की, जो अपने सौंदर्य के प्रति असावधान है, का रूपक बनकर वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रकट करती है। यह कविता परीक्षा के बुखार के दिनों में भी हमें एक अजीब उल्लास से भर देती थी और खिलखिलाकर हंसने पर विवश कर देती थी।

वसंत पंचमी महाकवि निराला की जयंती भी है। निराला अपना जन्मदिन वसंत पंचमी को ही मनाते थे। अपनी एक प्रसिद्ध कविता 'हिंदी के सुमनों के प्रति' में वह कहते हैं-*मैं ही वसंत का अग्रदूत।* देवी सरस्वती का संबंध भी वसंत पंचमी से है। हालांकि वसंत का संबंध कामदेव से भी है। कहा जाता है कि जिस दिन वसंत पृथ्वी पर अवतरित होता है, उसे वसंतावतार का दिन कहा जाता है और इसी दिन प्राचीन भारत में 'सुवसंतक' नामक उत्सव मनाया जाता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि 'इसी दिन मदन देवता की पहली पूजा विहित है। अच्छा तमाशा है-जन्म हो वसंत का और उत्सव मदन देवता का।'

खैर, हमारे देश में जितने भी पर्व-त्योहार मनाए जाते हैं, उनका संबंध प्रकृति से और कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उत्तर भारत के कई इलाकों में किसान इस दिन श्रीपंचमी का उत्सव मनाते हैं, जिसमें हल की पूजा की जाती है। धरती का असली शृंगार तो फसलों से ही होता है। कालिदास ने फसलों को कृषिफल कहा है। वसंत के मौसम में ही गेहूं की बालियां परिपक्व होकर पकने लगती हैं।

इसके अलावा, भूवैज्ञानिक भी कहते हैं कि घोर शीत ऋतु के बाद वसंत ऋतु में भूमध्य रेखा ठीक सूर्य के सामने आ जाती है। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश और उसकी ऊष्मा पृथ्वी पर सीधे पहुंचने लगती है। इस ऋतु में शीत तो दूर होती ही है, सूर्य की ऊष्मा पाकर पृथ्वी भी जग जाती है। उसकी चेतना जाग उठती है।

जब पृथ्वी यानी प्रकृति जगती है, तो पुरुष भी जगता है, समाज भी जगता है, उसकी इच्छाएं, भावनाएं जगती हैं। उसमें विवेक और काम भावना का संचार होता है। इस तरह से सूर्य और प्रकृति का जो संयोग है, वह प्रकृति पर तो असर डालता ही है, मनुष्य और उसके समाज पर भी उसका असर होता है। पेड़, पौधे, नदियां, पर्वत, मनुष्य, समाज सब की चेतना जाग जाती है। वसंत ऋतु में सिर्फ मनुष्यों की इच्छाएं ही नहीं जागतीं, बल्कि प्रकृति भी इच्छाओं और कामनाओं से भर उठती हैं। वसंत ऋतु में तरह-तरह के फूलों का खिलना प्रकृति की इन्हीं कामनाओं का प्रतीक है। हरे-भरे खेतों में सरसों के पीले फूल प्रकृति की सुषमा में चार चांद लगा देते हैं। इस तरह से वसंत ऋतु सृष्टि के सृजन और विकास को गति देती है। महाकवि निराला ने तो लिखा ही है-*रंग गई पग-पग धन्य धरा/ हुई जग जगमग मनोहरा।*

कहा जाता है कि वसंत में मन-प्राण खिल उठते हैं। हम लोग बचपन में देखते थे कि वसंत पंचमी के दिन से ही लोग एक-दूसरे को अबीर लगाना शुरू कर देते थे और सामूहिक रूप से होली गाई जाने लगती थी। वसंत के दौरान पूरे गांव-समाज में सामूहिकता की भावना व्याप्त दिखती थी। लेकिन आज सामूहिकता की वह भावना लगभग खत्म होती जा रही है। लोग आत्मकेंद्रित ज्यादा हो चले हैं और अपनी-अपनी दुनिया में सीमित होकर रहने लगे हैं। कहने को तो स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया में कहीं भी पल भर में संवाद कर सकते हैं, लेकिन अपने आस-पास से कटकर हम अकेले हो चले हैं।

प्रौद्योगिकी के विकास ने हमारे लिए अवसरों के अनेक द्वार तो खोले हैं, लेकिन हमारे सामने एक नया संकट भी खड़ा कर दिया है और वह संकट है-इकहरेपन का संकट। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों से कटते भी जा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है-*आह दबाओ यूं न समय की चट्टानों के नीचे-नीचे।* हमारे देखते-देखते भाषा के कितने शब्द लुप्त हो गए। हम अपनी समृद्ध और सकारात्मक परंपरा को भूलते जा रहे हैं। परंपरा इकहरी नहीं होती, वह हमेशा समृद्ध और बहुलतावादी होती है। इकहरापन रचना की भी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में, इकहरापन कभी सफल नहीं हो सकता। वसंत पंचमी के दिन हम इन सब चीजों पर जितना चिंतन करेंगे, उतना संभलेंगे। और संभलने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह आत्म सेवा के साथ समाज सेवा और देश सेवा भी है, क्योंकि जो खुद संभलेगा, वही तो दूसरों को संभाल सकता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

महात्मा गांधी

किसी प्राणी को चोट न पहुंचाना बेशक अहिंसा का अंग है, परंतु यह उसका छोटे से छोटा चिह्न है। अहिंसा के सिद्धांत को प्रत्येक बुरे विचार से, झूठ बोलने से, घृणा से, किसी का बुरा चाहने से आघात पहुंचता है।

अहिंसा साधन है सत्य साध्य है

सत्य का मार्ग जितना सीधा है, उतना ही तंग भी है। यही बात अहिंसा की है। यह खांडे की धार पर चलने के बराबर है। ध्यान की एकाग्रता के जरिये एक कलाकार रस्सी पर चल सकता है। परंतु सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहीं बड़ी एकाग्रता की जरूरत है। जरा-सा ध्यान चूके कि धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। सतत साधना के जरिये ही सत्य और अहिंसा को सिद्ध किया जा सकता है। लोगों ने अहिंसा को आज जो रूप दे रखा है, अहिंसा वैसी स्थूल चीज नहीं है। किसी प्राणी को चोट न पहुंचाना बेशक अहिंसा का अंग है, परंतु यह उसका छोटे से छोटा चिह्न है। अहिंसा के सिद्धांत को प्रत्येक बुरे विचार से, अनुचित जल्दबाजी से, झूठ बोलने से, घृणा से, किसी का बुरा चाहने से आघात पहुंचता है। जिस वस्तु की संसार को आवश्यकता है, उससे चिपटे रहने में भी अहिंसा भंग होती है। परंतु संसार को तो हम रोज जो कुछ खाते हैं उसकी भी जरूरत है।

जिस स्थान पर हम खड़े हैं, वहां लाखों कीटाणु हैं, जो उस स्थान के मालिक हैं और जिन्हें हमारे वहां होने से चोट पहुंचती है। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए? अगर हमारा यह विश्वास हो, जैसा कि है, कि जब तक शरीर के लिए आसक्ति बनी हुई है, तब तक एक शरीर के नष्ट होने पर आत्मा अपने लिए दूसरा शरीर तैयार कर लेती है, तो यह भी कोई हल नहीं है।

शरीर का बंधन तो तभी मिटेगा, जब हम उसकी आसक्ति छोड़ देंगे। आसक्ति से मुक्ति ही सत्यरूपी ईश्वर का साक्षात्कार है। यह साक्षात्कार जल्दबाजी से प्राप्त नहीं हो सकता। शरीर हमारा नहीं है। जब तक वह है, तब तक हमें उसे अपने को सौंपी हुई धरोहर समझकर उसका उपयोग करना चाहिए।

शरीर संबंधी बातों के प्रति यह दृष्टि रखकर ही हम किसी दिन शरीर के भार से मुक्त होने की आशा रख सकते हैं। शरीर की मर्यादाओं को अच्छी तरह समझकर हमें अपने भीतर जो भी शक्ति है, उसे लगाकर आदर्श की ओर दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

अहिंसा और सत्य आपस में इतने गुंथे हुए हैं कि उन्हें एक-दूसरे से सुलझाकर अलग करना लगभग असंभव है। वे एक सिक्के के या यों कहिए कि धातु के एक चिकने गोल टुकड़े के दो पहलुओं की तरह हैं। कौन कह सकता है कि यह उल्टा है और यह सीधा है? फिर भी, अहिंसा साधन है, सत्य साध्य है। साधन वही है, जो सदा हमारी पहुंच के भीतर हो, और इसीलिए अहिंसा हमारा सर्वोच्च धर्म है। अगर हम साधन को संभाल लें, तो हम साध्य तक देर या सवेर पहुंचकर ही रहेंगे। एक बार यह बात अच्छी तरह समझ लें, तो हमारी अंतिम विजय असंदिग्ध है। हमारे रास्ते में चाहे जो कठिनाइयां आएं, बाह्य दृष्टि से हमारी चाहे जितनी हार होती दिखे, हम सत्य की खोज न छोड़ें और विश्वास के साथ एक ही मंत्र जपें-सत्य है।

अहिंसा की शक्ति...

सूत्र

अहिंसा सर्वोच्च प्रकार की सक्रिय शक्ति है। वह आत्मबल या हमारे भीतर विराजमान भगवान की शक्ति है। अपूर्ण मानव उसके तेजपुंज को पूरा ग्रहण नहीं कर सकता। परंतु उसका लेशमात्र भी जब हमारे भीतर सक्रिय हो जाता है, तब वह गजब का काम करता है। आकाश का सूर्य सारे विश्व को अपनी प्राणदायक गरमी से भर देता है।

दूसरा पहलू

शुरुआती प्राइमेट्स ज्यादातर मृदु फल खाते थे, पर कुछ प्रजातियां बीज व अखरोट जैसी कठोर चीजें खाती थीं।

मनुष्य के आदिम पूर्वज थे मीठे फलों के शौकीन

हमारे पूर्वज रहे वानर और बंदर क्या खाते थे और इन शुरुआती प्राइमेट्स की आहार शैली का आधुनिक मनुष्य पर क्या असर पड़ा, यह लंबे समय से शोधकर्ताओं की जिज्ञासा का विषय रहा है। शोध यह बताते हैं कि शुरुआती प्राइमेट्स ज्यादातर मृदु फल खाते थे, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां जरूर ऐसी थीं, जो बीज व अखरोट जैसी कठोर चीजें खाती थीं। पर आधुनिकतम रिसर्च बताती है कि हमारे पूर्वज वानर ज्यादातर पके हुए मीठे फल खाते थे। मिस्र से प्राइमेट्स के जो करीब तीन करोड़ साल पुराने अवशेष मिले हैं, उनके दांतों का क्षय इसकी पुष्टि करता है।

कैरोलिना लोच

अमूमन मनुष्यों को वानर श्रेणी से बाहर माना जाता है और वानरों को भी बंदर नहीं समझा जाता है। फिर भी मनुष्य वानर परिवार में ही शामिल होता है, जो व्यापक बंदर समूह में वर्गीकृत होता है।

प्राइमेट परिवार पर चर्चा करते वक्त बंदर और वानर (एप) में फर्क समझना जरूरी है। हालांकि इसे परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन अमूमन मनुष्यों को वानर श्रेणी से बाहर माना जाता है और वानरों को भी बंदर नहीं समझा जाता है। फिर भी मनुष्य वानर परिवार में ही शामिल होता है, जो व्यापक बंदर समूह में वर्गीकृत होता है। इन सभी प्राइमेट्स (मनुष्य, वानर और बंदर) को सामूहिक रूप से एंथ्रोपॉइड कहा जाता है, और हम सभी एक सामान्य एंथ्रोपॉइड के वंशज हैं, जो लगभग चार करोड़ साल पहले रहता था।

जीवाश्म-साक्ष्य बताते हैं कि ढाई से चार करोड़ वर्ष पहले की अवधि एंथ्रोपॉइड के विकास और प्रसार का महत्वपूर्ण चरण थी। इस वक्त के सर्वाधिक जीवाश्म मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में मिलते हैं। उन्तीस से साढ़े पैंतीस करोड़ साल पुराने ये जीवाश्म तब के हैं, जब यह रेगिस्तान हरा-भरा हुआ करता था। पारिस्थितिकी तंत्र के अवशेषों को संरक्षित करने वाली यहां की चट्टानें, जिन्होंने अफ्रीका की आधुनिक जैव-विविधता के लिए आधार तैयार किया, प्राइमेट्स के विकास को समझने की महत्वपूर्ण जगह भी हैं। यहां से मिले शुरुआती एंथ्रोपॉइड के जीवाश्म की खोपड़ी और जबड़ा उनके आहार-व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। जीवाश्मों के दांतों की स्थिति बताती है कि उस वक्त के प्राइमेट्स सुकोमल मीठे फलों को ही पसंद करते थे। दांतों के जो अवशेष मिले हैं, वे केवल पांच फीसदी तक ही सड़े हैं, बाकी बिल्कुल स्वस्थ हैं। जबकि ज्यादातर आधुनिक एंथ्रोपॉइड में दांतों के टूटने की आवृत्ति चार से चालीस फीसदी तक है। यह शोध पिछले शोधों की भी पुष्टि करता है, जिनके अनुसार प्रारंभिक मानववंशी वनस्पति आधारित जीवन-शैली पर निर्भर थे। निष्कर्ष यह भी है कि हमारे पूर्वजों को फलाहार से दूर जाने में काफी वक्त लगा। *(कन्वर्सेशन से)*

आंकड़े

कहां से लेते हैं कच्चा तेल

भारत पहले खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता था, लेकिन अब रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात होता है।

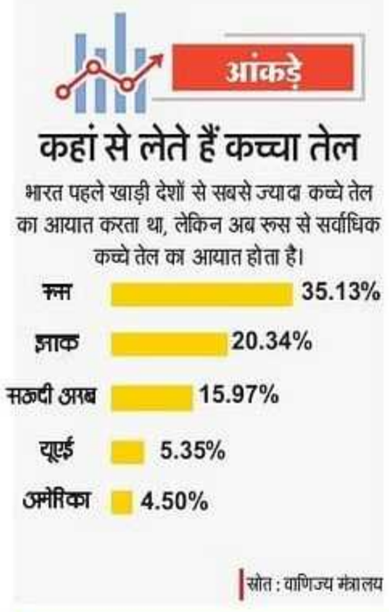

स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय

जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा के तारों को छुआ, उससे संगीत के प्रथम सुर 'सा' का जन्म हुआ। इसके साथ ही ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा।

ऐसे प्रकट हुईं देवी सरस्वती

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई सृष्टि को देखा, तो उन्हें लगा कि सब मूक, शांत और नीरस है, जिसमें न तो कोई स्वर है और न वाणी।

अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी निराश हो गए और भगवान विष्णु को अपनी समस्या के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि आप देवी सरस्वती का आह्वान कीजिए। आपकी समस्या का समाधान वही कर सकती हैं। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। देवी सरस्वती हाथों में वीणा लेकर प्रकट हुईं। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा के तारों को छुआ, उससे संगीत के प्रथम सुर 'सा' का जन्म हुआ। 'सा' स्वर के कंपन से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। पूरी सृष्टि को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए।

उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम दिया। हाथों में वीणा होने के कारण मां सरस्वती वीणापाणि भी कहलाईं। मां सरस्वती वसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थीं, इसलिए वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा होती है।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 31 जनवरी, 1955

स्टील के नए कारखाने खोलने पर समझौता

स्टील के कारखाने के खोलने का प्रश्न

रूस से पूर्ण समझौता

नई दिल्ली, 1० जनवरी। भारत व रूस की सरकारों के बीच स्टील के नये कारखाने के निर्माण करने पर जो समझौता हुआ है उस पर मंगलवार को हस्ताक्षर हो जायेंगे।

बताया जाता है कि स्टील के कारखाने के बारे में जो मत भेद थे वे वार्ता के बाद समाप्त होगये। समझौते पर हिन्दी, रूसी व अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर होंगे। यह कारखाना...

भारत और रूस की सरकारों के बीच स्टील के नए कारखाने खोलने पर समझौता हुआ है। बताया जाता है कि इसके बारे में जो मतभेद थे, वे वार्ता के बाद समाप्त हो गए हैं। यह कारखाना मध्य प्रदेश में खोला जाएगा।

देश में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं

दिल्ली-एनसीआर के संदर्भ में भू-वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे-छोटे कंपनों से भूगर्भीय ऊर्जा निकल जाती है एवं बड़े भूकंप का खतरा कम हो जाता है।

ओ. पी. जोशी

भूविज्ञान

भूवैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप के यूरेशियन प्लेट से टकराने के फलस्वरूप धरती हिलती-डुलती है और भूकंप आते हैं। इसके अलावा धरती के भीतर की ऊर्जा के दबाव से भी भूकंपन होता है। लेकिन इसके प्रभाव-क्षेत्र में इंसानी बसाहट होने से परिणाम दुखद होते हैं। ऐसे में, इस संबंध में किए जाने वाले शोधों के लिहाज से यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि भूकंपन की आवृत्ति कितनी है? उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 के 365 दिनों में से 34 दिन देश में कहीं-न-कहीं भूकंप की घटनाएं होती रही हैं। यहां तक कि पिछले वर्ष का पहला व अंतिम दिन भी भूकंप से प्रभावित रहा है।

भूगर्भ विशेषज्ञों ने भारत के करीब 59 फीसदी भू-भाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। पिछले वर्ष एक जनवरी को दिल्ली से हरियाणा तक 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके रात 1.30 बजे दर्ज किए गए। पिछले वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर को भी दोपहर 2.30 पर 3.6 तीव्रता के

झटके मध्य प्रदेश के सिंगरौली में महसूस किए गए। यहां 26 दिसंबर को भी कुछ झटके आए थे। मई को छोड़कर शेष सभी महीनों में देश के 14 राज्यों के 30 शहरों में 2.0 से 6.6 तीव्रता के झटके आए, परंतु कोई बड़ी जन-हानि नहीं हुई। दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तरकाशी एवं मणिपुर क्रमशः नौ, पांच, चार एवं दो बार झटकों से प्रभावित हुए। देश के उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र में ज्यादा झटके आए। कुछ भूकंप के क्षेत्र काफी व्यापक भी रहे। 24 जनवरी को दोपहर 2.30 पर 30 सेकंड तक दिल्ली-एनसीआर में 5.3 तीव्रता के झटके आए। इन झटकों का प्रभाव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ भागों में देखा गया।

19 फरवरी को मध्य प्रदेश के धार, बड़वानी, अलिराजपुर सहित कई जिलों में दोपहर 12.45 पर छह सेकंड तक तीन से चार तीव्रता के झटके आते रहे। इसका केंद्र धार जिले में 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। दो अप्रैल को प्रातः जबलपुर, नर्मदापुरम एवं पचमढ़ी में 3.6 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। नर्मदापुरम में 21 मार्च की रात को भी कुछ झटके आए थे। 21 मार्च को दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में रात 10.20 पर 6.6 तीव्रता का कंपन हुआ था। तीन अक्तूबर को दोपहर में फिर दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कंपन हुआ। इस भूकंप की तीव्रता 5.3 से 6.3 रेक्टर पैमाने पर आंकी गई।

इसी दिन नेपाल में भी शाम को चार से पांच तीव्रता के झटके आने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए एवं 10 लोग घायल हुए। गुजरात के कच्छ एवं राजकोट में 30 जनवरी एवं दो फरवरी को 4.3 तीव्रता के झटके आए, परंतु कोई हानि नहीं हुई। मणिपुर के उखरूल व विष्णुपुर में चार फरवरी व 16 अप्रैल को हल्के झटके दर्ज किए गए।

छत्तीसगढ़ के गौरला-पेंड्रा-मरवाही और कोरबा जिले के गांवों में 13 अगस्त की रात एवं सरगुजा तथा अनूपपुर में 28 अगस्त को भूकंप आया। कलबुर्गी (कर्नाटक), जोरहाट (असम), बीकानेर (राजस्थान), बिजनौर व अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में क्रमशः 18 जनवरी, 18 मार्च, 25 मार्च, तीन अप्रैल व पांच नवंबर को हल्के झटके आए।

हिमालयी क्षेत्र एवं दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते भूकंपों के संदर्भ में भू-वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे-छोटे कंपनों से भूगर्भीय ऊर्जा निकल जाती है एवं बड़े भूकंप का खतरा कम हो जाता है। हिमालय के नीचे स्थित 'यूरेशियन प्लेट' के 'इंडियन प्लेट' से टकराने से 200 किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली-एनसीआर में कुछ भ्रंश (फाल्ट) बन गए हैं, जिनके कारण इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा झटके आ रहे हैं।

दूसरी ओर, मध्यभाग के संदर्भ में भूकंप वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां भी 'टेक्टोनिक प्लेट्स' में हो रही हलचल से झटके आ रहे हैं। खंडवा एवं नर्मदा नदी से जुड़े जिले ज्यादा संवेदनशील बताए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भी नर्मदा व सोन नदी घाटी वाले जिलों में ज्यादा खतरा बताया है। इन जिलों में पिछले तीन वर्षों में 38 झटके दर्ज किए गए हैं। बढ़ता भूकंप देश के लिए एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। अतः गंभीरता से ध्यान देकर ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि जानमाल की हानि कम-से-कम हो।

(सप्रेस)

For More Newspapers And Magazines Join Paid Group 8969469464

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 14 फरवरी, 2024

दैनिक जागरण

ज्ञान से बड़ी शक्ति और संपदा कोई और नहीं

फिर दिल्ली कूच

आम चुनाव के पहले पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन कई सवाल खड़े करता है। चार साल पहले भी तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन मुख्यतः पंजाब से ही शुरू हुआ था। बाद में उसमें हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन भी शामिल हो गए थे। यह समझना कठिन है कि जो किसान देश में सबसे समृद्ध माने जाते हैं और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सबसे अधिक लाभ उठाते हैं, वे ही बार-बार आंदोलन का सहारा क्यों लेते हैं? इस सवाल के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चार वर्ष पहले पंजाब के किसान संगठनों को आंदोलनरत करने में कांग्रेस की तत्कालीन अमरिंदर सिंह सरकार की प्रमुख भूमिका थी। इस बार किसान संगठनों के आंदोलन का कांग्रेस भी खुलकर समर्थन कर रही है और पंजाब एवं दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी। यह तय है कि आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी दल भी किसान संगठनों के पक्ष में खड़े नजर आएंगे, क्योंकि चुनाव के इस मौके पर हर दल खुद को किसान हितैषी दिखाना चाहेगा। किसानों की अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं और हैं भी, लेकिन आखिर जब सरकार बातचीत के जरिये उनका समाधान निकालने को तैयार है तो फिर दिल्ली चलो अभियान पर जोर देने का क्या औचित्य? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि केंद्र सरकार के मंत्रियों और पंजाब के किसान नेताओं के बीच वार्ता इसीलिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि किसान संगठनों का इरादा दिल्ली कूच करने का अधिक था। शायद इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी भी मांगे रखीं, जिन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना संभव नहीं।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाले कानून के साथ किसान संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि 60 वर्ष की आयु के बाद हर किसान को प्रति माह दस हजार रुपये की पेंशन दी जाए। आखिर इस तरह की मांग करने वाला कोई भी किसान संगठन यह दावा कैसे कर सकता है कि वह तो अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलनरत है? किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर प्रश्न खड़े करना बहुत आसान है, लेकिन क्या कोई इसे भूल सकता है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान किस तरह लाल किले में भीषण हिंसा की गई थी और राजमार्गों पर कब्जा कर दिल्ली-एनसीआर के लोगों की जीवनचर्या को कितनी बुरी तरह बाधित किया गया था? क्या कोई किसान संगठन या उनके समर्थन में खड़े दल यह भरोसा दिलाने को तैयार हैं कि इस बार वह सब नहीं किया जाएगा, जो पहले किया गया था? निःसंदेह कुछ प्रश्नों के जवाब केंद्र सरकार को भी देने होंगे और सबसे प्रमुख प्रश्न यही है कि तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान संगठनों से जो वायदे किए गए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में क्या किया गया?

मानसिकता पर सवाल

जनहित में सरकार कई योजनाएं बनाती है। इन्हें धरातल पर उतारने का दायित्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर होता है। इन्हें जनता और सरकार के बीच की कड़ी भी माना जाता है। पारदर्शी प्रशासन हर सरकार का प्रयास रहता है। सरकार ने लोगों को कई विकल्प भी दिए हैं कि यदि कहीं पर किसी तरह की अव्यवस्था हो तो शिकायत की जा सकती है। कर्मचारियों और अधिकारियों को यथासंभव वेतन तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बावजूद भ्रष्टाचार के मामले सामने आना उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। यदि कोई व्यक्ति मांग पूरी नहीं करता है तो उसका काम लटकाया जाता है। उनकी इस हरकत से सभी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते हैं। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पटवारी पर आपदा राहत राशि जारी करने की एवज में 50 हजार रिश्वत लेने और 50 हजार रुपये की मांग करने का आरोप लगा था। सोमवार को ऊना जिला की टाहलीवील नगर पंचायत के क्लर्क को विजिलेंस ब्यूरो ने छह हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि क्लर्क ने ठेकेदार से बिल की राशि जारी करने की एवज में मांगे थे। उधर बिलासपुर स्थित एम्स में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के लिए स्टोर कीपर पर लोगों से 40-40 हजार रुपये लिए जाने का आरोप लगा है। प्रश्न यह है कि जब काम के बदले वेतन दिया जाता है तो कुछ रुपये के लिए घटिया कार्य क्यों किया जाता है। होना तो यह चाहिए कि कार्य को ईमानदारी से किया जाए। यदि किसी कमी के कारण किसी व्यक्ति का कार्य बाधित हो रहा है तो उसे हल करवाया जाना चाहिए। लोगों को भी जागरूक होकर ऐसे लोगों की शिकायत तत्काल संबंधित पक्षों से की जानी चाहिए।

भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए लोगों को आगे आना होगा। लोगों की जागरूकता से ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है

समान नागरिक संहिता का अतार्किक विरोध

ए. सूर्यप्रकाश

समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम समुदाय के नेताओं के विरोध का रवैया बिल्कुल वैसा ही है जैसा संविधान सभा के उसके सदस्यों का था

अवधेश राजपूत

अंततः उत्तराखंड के रूप में किसी राज्य ने समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल की है। जैसा कि अनुमान था, मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं ने उसका विरोध शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि उनके समुदाय को इससे बाहर रखा जाए। जमीयत-उलमा-ए-हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान शरीयत के खिलाफ कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून को संविधानप्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया। देहरादून में स्थानीय स्तर पर भी विरोध हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को मुस्लिम समुदाय की इन आपत्तियों के आगे समर्पण कर देना चाहिए या पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के व्यापक हितों को प्रोत्साहित करना चाहिए? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक और विरासत-उत्तराधिकार से जुड़े नागरिक कानूनों में समरूपता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुस्लिम पर्सनल ला के अनुसार किसी मुसलमान पुरुष की एक ही समय में चार पत्नियां हो सकती हैं। यह बहुविवाह की स्थिति अनुच्छेद-14 के अंतर्गत मिली 'विधि के समक्ष समता' के अधिकार का उल्लंघन करने के साथ ही महिलाओं की गरिमा पर आघात करती है। यह लैंगिक समानता के मूलभूत सिद्धांत का भी उल्लंघन है।

अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज के मौजूदा नेताओं का रवैया संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों से कतई अलग नहीं, जिन्होंने 76 साल पहले भी ऐसी संहिता का मुखर विरोध किया था। तब संविधान सभा बस इतनी व्यवस्था करके रह गई कि 'राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा।' यह प्रविधान सलाह के स्वरूप में ही था, लेकिन संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। इस मुद्दे पर 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में तीखी बहस हुई। आरंभ में इसे संविधान के अनुच्छेद-35 के रूप में जोड़ने का विचार था, लेकिन बहस के बाद यह अनुच्छेद-44 के रूप में अस्तित्व में आया। बहस की शुरुआत करते हुए मोहम्मद इस्माइल साहिब ने कहा था कि किसी भी समूह के पर्सनल ला में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही संशोधन रखते हुए महबूब अली बेग साहिब बहादुर ने कहा कि पर्सनल कानूनों के पालन का अधिकार एक मूल अधिकार है। उनका दावा था कि यूरोपीय देशों ने भी मुस्लिमों को इस प्रकार की रियायत प्रदान की है। बी. पोकर साहिब बहादुर ने संशोधनों का समर्थन करते हुए उक्त अनुच्छेद को 'दमनकारी' करार दिया था, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मजहबी परंपराओं में हस्तेक्षप करते हुए लोगों की चेतना को कुचलता है। इमाम हुसैन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि समान नागरिक संहिता संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करती है। इस प्रकार संविधान सभा के जो अन्य मुस्लिम सदस्य इस मुद्दे पर बोले, सभी ने इसका विरोध किया। केएम मुंशी ने उनकी आपत्तियों का प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-25 धार्मिक परंपराओं और 'सामाजिक कल्याण एवं सुधार' के आलोक में राज्य को 'सेक्युलर गतिविधि' से संबंधित कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। इसीलिए, अनुच्छेद-44 सरकार को नागरिक कानूनों में एकरूपता के प्रयास की गुंजाइश प्रदान करता है। संहिता को 'दमनकारी' कहने वाले सदस्यों के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम देश में अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों को इतना अटल नहीं माना गया है। तुर्की और मिस्र का उदाहरण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वहां किसी अल्पसंख्यक को ऐसे निजी कानूनों की अनुमति नहीं। यहां तक कि भारत में खोजा और मेमन जैसे वर्ग भी असंतुष्ट हैं कि उन पर शरीयत कानून थोपा हुआ है।' उन्होंने पूछा कि तब अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या? उन्होंने दो-टूक कहा कि हम धर्म-पंथ-मजहब को निजी कानूनों से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने हिंदुओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वे मनु और याज्ञवल्क्य की परंपराओं से मुक्त हो रहे हैं तो मुसलमानों को भी 'जीवन के प्रति अलगाववादी दृष्टिकोण' त्याग देना चाहिए। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि हिंदू संहिता में प्राचीन हिंदू कानूनों को तिलांजलि दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने समय के अनुरूप ढलना उचित समझा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग इस्लामिक आपराधिक कानूनों की मांग क्यों नहीं की?

संविधान सभा में डा. बीआर आंबेडकर ने भी मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम सदस्यों के तर्क सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि देश में मानवीय संबंधों के लगभग सभी पहलुओं को अपने दायरे में समेटने वाली कानूनी संहिताएं हैं। इनमें समान आपराधिक संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और व्यावहारिक रूप से समान नागरिक संहिता भी शामिल है, जिसमें केवल विवाह और उत्तराधिकार के मुद्दे पर पेच फंसा है। उन्होंने सभा को स्मरण कराया कि 1939 तक नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं होते थे। विरासत इत्यादि के मामले वे हिंदू कानूनों का पालन करते रहे। इसी प्रकार 1937 में शरीयत कानून पारित होने से पहले तक उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत एवं बांबे प्रांत में भी मुस्लिम समुदाय विरासत से जुड़े हिंदू कानूनों का पालन करता रहा तो मालाबार के मुसलमान हिंदू मातृसत्तात्मक कानूनों का। उन्होंने कहा कि इन आधारों पर मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियां खारिज की जाती हैं।

इस प्रकार देखें तो 1947 में मजहबी आधार पर देश विभाजन के बावजूद जो मुस्लिम भारत में रह गए थे वे भी केएम मुंशी जैसे विद्वान की दृष्टि में एक प्रकार के 'अलगाववादी' सोच से प्रेरित थे। उसी प्रकार का सोच वर्तमान में समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है। समान नागरिक संहिता के विरोध में तमाम कुतर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में यदि भारत को उदार एवं लोकतांत्रिक समाज बने रहना है तो समान नागरिक संहिता के विरोध में मुस्लिम समाज की आपत्तियों को चुनौती देकर उनका प्रभावी प्रतिकार करना समय की आवश्यकता है। बहुसंख्यक समाज को भारत की पंथनिरपेक्षता, उदारता एवं लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आगे आकर मुखर होना होगा, भले ही इसके चाहे जो परिणाम निकलें।

(लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

आशंकित करता एक और आंदोलन

राजीव सचान

किसानों को भी दिल्ली आकर अपनी बात कहने का हक है, पर जनजीवन बाधित करने का अधिकार किसी को भी नहीं

लोगों के लिए संकट खड़ा करता आंदोलन। प्रेट्र

पता नहीं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आने पर अड़े विभिन्न किसान संगठन राजधानी में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि उनके दिल्ली कूच के चलते दिल्ली और आसपास के शहरों में यातायात बाधित होना शुरू हो गया है। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली को घेरने की तैयारी हो रही है। इसके पहले तीन कृषि कानूनों के विरोध में भी दिल्ली को घेरा गया था। पिछली बार भी कृषि कानून विरोधी आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था। तब वहां अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, जो बाद में भाजपा में चले गए। अक्टूबर 2020 में पंजाब के किसान संगठन रेल पटरियों पर कब्जा कर बैठ गए। इसके चलते पंजाब के उद्योगों को अच्छा-खासा नुकसान हुआ। फिर किसानों ने मोबाइल टावर तोड़ने शुरू कर दिए गए, क्योंकि इन कानूनों को अंबानी-अदाणी कानून करार दिया गया था। करीब 1500 मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त किए गए। फिर अमरिंदर सिंह ने किसान संगठनों को समझाया कि कृषि कानून तो भारत सरकार ने बनाए हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली जाना चाहिए। वे नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर आ डटे। किसान संगठनों का मनोबल तब और बढ़ा, जब जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों की वैधानिक समीक्षा किए बगैर उनके अमल पर रोक लगा दी। उसने इन कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति भी गठित कर दी। किसान संगठनों ने इस समिति को खारिज कर दिया और वे दिल्ली घेरकर बैठे रहे। इसी बीच 26 जनवरी आई तो किसान संगठनों ने इस बहाने ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की कि उन्हें भी अपने तरीके से गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत खुलेआम धमकी दे चुके थे कि यदि किसी ने ट्रैक्टर रोके तो बक्कल उतार देंगे। इसका मतलब जो भी होता हो, लेकिन 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर पर सवार कथित किसानों ने सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बार्डर से दिल्ली में घुसकर हिंसा का नंगा नाच किया। उन्होंने लाल किले पर धावा बोल दिया। अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने संयम बरता, लेकिन इसके बदले उन्हें पिटना पड़ा। इस पिटाई में कई पुलिस वाले घायल हुए।

लाल किले में देश को शर्मसार करने वाली हिंसा से कृषि कानून विरोधी आंदोलन बदनाम हुआ और कुछ किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन अन्य संगठन धरने पर बैठे रहे और दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों की नाक में दम किए रहे। हरियाणा और यूपी के लोगों को दिल्ली आने-जाने में घंटों का समय जाया करना पड़ता था। उनके समय और संसाधन की बर्बादी होती थी, लेकिन किसान संगठन इस सबसे बेपरवाह रहे। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए किसान नेताओं को वार्ता के लिए निमंत्रण देती रही, लेकिन वे इसी पर अड़े रहे कि इन कानूनों के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इसके चलते किसान नेताओं और मोदी सरकार के बीच 11 दौर की जो वार्ता हुई, वह नाकाम रही। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने कृषि कानूनों पर अपनी रपट उसे सौंप दी, लेकिन उसने उसका संज्ञान ही नहीं लिया। उसने अपनी ही समिति की रपट को अनदेखा कर दिया।

जब अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की कार से चार किसान कुचल कर मर गए और इसके बाद भड़की हिंसा में चार और लोग मारे गए तो किसान आंदोलन फिर से गर्म हो उठा। आखिरकार नवंबर 2021 में गुरु परब के दिन प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की कि ये कानून अच्छे थे, छोटे किसानों की भलाई के लिए थे, लेकिन सरकार उनके लाभ समझाने में सफल नहीं रही। यह घोषणा किसानों के हितों की बलि लेने वाली थी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा ने किसानों को उसी स्थिति में धकेल दिया, जहां वे पहले थे। ये कानून ठीक वैसे ही थे, जैसे कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में बनाने का वादा किया था।

कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ समय बाद किसान संगठन दिसंबर 2021 में इस आश्वासन के बाद ही लौटे कि आंदोलन के दौरान मरे किसानों के स्वजनों को मुआवजा दिया जाएगा और उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। क्या ये आश्वासन खोखले थे? सरकार को बताना चाहिए कि क्या उसने ये आश्वासन पूरे किए? यदि नहीं तो क्यों? इसी के साथ यह भी ठीक नहीं कि कोई संगठन या संगठनों का समूह इस पर अड़ जाए कि वह जो भी मांगें कर रहा है, उन्हें जस का तस मान लिया जाए।

नया किसान आंदोलन चाहे जो करवट ले, इसे भूला नहीं जा सकता कि पुराने किसान आंदोलन के चलते जगह-जगह नाकाबंदी से हजारों करोड़ रुपये की बर्बादी हुई। इसके अलावा उस आंदोलन में बंगाल से शामिल होने आई एक युवती से आंदोलनकारियों ने ही टिकरी बार्डर पर दुष्कर्म किया। टिकरी बार्डर पर ही झज्जर के एक किसान को जिंदा जला दिया गया। सिंघु बार्डर पर पंजाब के एक युवक लखबीर सिंह को अंग-भंग करके उसके शव को बैरिकेड पर लटका दिया गया था। क्या कोई गारंटी लेने को तैयार है कि इस बार ऐसा कुछ होने के साथ लाल किले जैसी हिंसा नहीं होगी? पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन यह ठीक नहीं कि लोगों को अव्यवस्था-अराजकता से बचाने के लिए दिल्ली की किलेबंदी करनी पड़ी।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विद्या की शक्ति

वसंत पंचमी की मान्यता ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की कृपा पाने के पर्व के रूप में है। यह तिथि निर्धारित करते समय मनीषियों ने मनुष्य की पंच ज्ञानेंद्रियों पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि, श्रवण, शब्द, स्वाद और स्पर्श के लिए आंख, कान, नासिका, जिह्वा तथा त्वचा ज्ञानेंद्रियां ही उसके मन और बुद्धि को प्रभावित करती हैं। इन पंच ज्ञानेंद्रियों पर मां सरस्वती की कृपा रहे एवं बुद्धि-विवेक जागृत रहे ताकि वह सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सके। सरस्वती शब्द की उत्पत्ति ही संस्कृत के 'सृ' धातु के 'सरस्' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्रवाहमान है। इस दृष्टि से इसका अर्थ सरोवर होता है। मनुष्य का शरीर भी सरोवर जैसा ही है। शरीर में लगभग 71 प्रतिशत जल तत्व है। इन्हीं जल तत्वों में कई जीवाणु वैसे ही पलते हैं जैसे सरोवर में। शरीर रूपी सरोवर में पवित्रता रहने से ही बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें कमी आने पर मानसिक उलझन होती है।

माघ संधिकाल का समय है। शीत की लहरें कम होने लगती हैं। भगवान भास्कर पुनः नजदीक आने लगते हैं। वसंत पंचमी तिथि भी माघ माह के गुप्त नवरात्र के बीच आती है। इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है कि मनुष्य प्रकृति में व्याप्त गुप्त क्षमताओं का अवगाहन कर सुयोग्य हो सके। मां सरस्वती के हाथ में पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है तो माला निरंतर साधना का सूचक। यह साधना की माला है। दो हाथों में वीणा का रूप मनुष्य के उलटे स्वरूप यानी शीश नीचे एवं पैर ऊपर की तरह है। मनुष्य वाह्य आकर्षणों को उलटा कर दे तो अंतर्जगत की शक्तियों का अधिष्ठाता स्वयमेव हो जाएगा। वीणा में सात तार ज्ञानेंद्रियों के सप्तद्वार हैं। मां सरस्वती श्वेत वस्त्र पहनती हैं जो सात्विकता का प्रतीक है, जबकि आसन का पीला वस्त्र ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान ही सबसे बड़ा वरदान है।

सलिल पांडेय

बनारस का अनोखा भारत माता मंदिर

सुधीर कुमार

इस मंदिर में भारत माता की छवि को ठोस रूप देने के लिए गर्भगृह में अखंड भारत का भू-मानचित्र बनाया गया है

बनारस का भारत माता मंदिर अपने तरह का एक विशिष्ट मंदिर है। यहां किसी भी धार्मिक देवी-देवता की मूर्ति नहीं है। फिर भी इसकी ख्याति एक मंदिर के रूप में है। इसकी वजह है कि पहली बार इस मंदिर में भारत माता की छवि को ठोस रूप देने के लिए गर्भगृह में अविभाजित भारत (अखंड भारत) का भू-मानचित्र बनाया गया है। इसमें नदियों, पर्वतों और मैदानी भागों को भी दर्शाया गया है। यह मानचित्र केंद्रीय कक्ष की फर्श पर मकराना के संगमरमर में खुदी हुई है। मानचित्र को बनाने में संगमरमर के साढ़े सात सौ से भी अधिक वर्गाकार टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसे 30 मूर्तिकारों और 25 राजमिस्त्रियों ने मिलकर बनाया है।

भारत माता मंदिर के स्थापना की कल्पना देश में सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त (1883-1944) ने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधीजी के आह्वान पर डा. भगवान दास (1869-1958) के साथ उन्होंने 'महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ' की स्थापना की थी। इसी विश्वविद्यालय के परिसर में भारत माता मंदिर अवस्थित है। यह एक राष्ट्रीय विरासत स्मारक है। यह एक ऐसा मंदिर है, जिसके प्रांगण में प्रवेश के साथ ही देशभक्ति की भावनाएं जोर मारने लगती हैं। मंदिर की छत पर लहराता तिरंगा झंडा जहां हर देशवासी को गर्वित करता है, वहीं मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश के साथ ही दीवार पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित भारत का राष्ट्रीय गीत-वंदे मातरम्, आगंतुकों में राष्ट्रीयता का संचार करता है। एक स्तंभ पर भारत माता की तस्वीर बनी है। गर्भगृह में बनी भारत माता की मानचित्र के रूप में उनकी मूर्ति स्थापित है। यह देश का इकलौता मंदिर है, जहां केवल भारत माता की ही अराधना होती है। देश के विभिन्न हिस्सों और विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए यह मंदिर आकर्षण का केंद्र है। चूंकि इस मंदिर में भारत माता की मानचित्र के रूप में उनकी प्रतिकात्मक मूर्ति स्थापित है, इसलिए प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस भू-मानचित्र में दिखाए गए जलाशयों में पानी भरा जाता है तथा मैदानी इलाकों को फूलों से सजाया जाता है।

शिव प्रसाद गुप्त ने बनारस के इस भारत माता मंदिर का शिलान्यास भगवान दास के हाथों से 1918 में करवाया था। वर्ष 1936 में इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। भारत में पहली बार उभारदार मानचित्र को प्रस्तुत करने का श्रेय शिव बाबू को ही जाता है। भारत माता मंदिर शिव बाबू की देशवासियों को एक ऐसी देन है, जिसके लिए पूरा देश उनका सदियों तक शुक्रगुजार रहेगा। किसी मंदिर के गर्भगृह में भारत माता को स्थान देना भारतीयों का भारत माता के प्रति लगाव को परिलक्षित करता है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

आर्थिक कायाकल्प की कहानी

'भारत के आर्थिक उत्थान का दस्तावेज' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा ने हाल में आए श्वेत पत्र के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का विवरण बहुत सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संप्रग सरकार के दौरान खराब आर्थिक नीतियों का खामियाजा देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। ऊपर से बेलगाम भ्रष्टाचार ने स्थितियों को और बिगाड़ दिया था। इससे एक समय नीतिगत पंगुता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जहां विकास से जुड़ी परियोजनाएं या तो सिरे नहीं चढ़ पा रही थीं या जिनका काम पहले शुरू हो गया था वह बीच में ही अटक गया। लेखकों ने पूंजीगत व्यय जैसे बिंदु की ओर भी उचित ही ध्यान आकृष्ट कराया है। मोदी सरकार के दौरान ऐसे गुणवत्तापरक एवं चक्रीय प्रभाव वाले खर्च बढ़ने के प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। सरकार वित्तीय अनुशासन से भी कोई समझौता करती नहीं दिख रही। अंतरिम बजट इसका एक बड़ा उदाहरण रहा, जहां सरकार ने कोई लोकलुभावन या चुनावी घोषणा नहीं की। यही कारण है कि घरेलू और वैश्विक निवेशकों का भारत में भरोसा बहाल हुआ है। एक समय 'फ्रैजाइल फाइव' यानी पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाने वाला भारत आज कोविड महामारी और एक के बाद एक युद्धों की अनिश्चित वैश्विक स्थिति के बीच विश्व की उम्मीदों का केंद्र बना हुआ है।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

मेलबाक्स

कांग्रेस को मुक्त करे गांधी परिवार

किसी भी दल या व्यक्ति के राजनीति में आने का घोषित उद्देश्य राष्ट्र सेवा होता है। आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। सोनिया गांधी-मेनका गांधी जेठानी-देवरानी हैं, पर दोनों में वर्षों से भेंट नहीं हुई है। राहुल गांधी-वरुण गांधी चचेरे भाई हैं, पर दोनों संपर्क में नहीं हैं। राहुल गांधी को उनके मित्र मिलिंद देवड़ा, हार्दिक पटेल, आरपीएन सिंह, अशोक चह्वाण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकोर छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। यूपीए के शासनकाल में करोड़ों रुपये के घोटाले हुए। एनपीए बेतहाशा बढ़ गया था। भारत की गिनती उन पांच देशों में होने लगी थी, जिनकी आर्थिकी बदहाली निरंतर बढ़ रही थी। भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनुशासनहीनता चरम पर थी। स्वयं सोनिया, राहुल गांधी आज बेल पर हैं। राहुल गांधी जब अपने परिवारजनों से संबंध नहीं रख पा रहे हैं, अपने मित्रों एवं कांग्रेसियों को पार्टी में नहीं रोक पा रहे हैं और यह भी देखते हुए कि उनकी पार्टी के शासनकाल में देश की आर्थिकी की कितनी दुर्गति हुई थी, उनको भारत के हित में अपने परिवार सहित कांग्रेस से किनारा कर लेना चाहिए। कांग्रेस वंशवाद के दंश से रसातल में है। गांधी परिवार कांग्रेस से अपने को पृथक कर ले तो संभवतः पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

सामाजिक सहयोग जरूरी

'माहौल बिगाड़ने वाले बयान' शीर्षक आलेख में अवधेश कुमार ने सामाजिक एकता के महत्व पर जोर दिया है, जो समाज के विभाजन को रोकने के लिए आवश्यक है। उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को भी उजागर किया है, जो एक समृद्ध समाज की नींव होती है। यह बात सत्य है कि अधिकतर मुस्लिम संगठनों और नेताओं के द्वारा की गई बयानबाजी न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह समाज के सौहार्द को बाधित भी कर सकती है। इन बयानों के माध्यम से जो दुर्भावनापूर्ण और आपत्तिजनक तथ्य फैलाए जा रहे हैं, वे न केवल सामाजिक तानेबाने को खतरे में डाल सकते हैं, बल्कि न्याय व्यवस्था को भी संकट में डाल सकते हैं। इस प्रकार की बातों के प्रसार से समाज में असंतोष पैदा होता है और लोगों में तनाव बढ़ता है। आज के समय में न्याय और संविधान के महत्व को समझना और स्वीकार करना हम सभी नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

awanishg30@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सैक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

162 प्रतिशत बढ़ा है देश में पिछले पांच साल में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन। हमारी ऊर्जा जरूरत में 158.12 गीगावाट (लगभग 40 प्रतिशत) हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की है।

अरविंद कुमार मिश्रा
लोक नीति विश्लेषक

भारत ऊर्जा सप्ताह

ऊर्जा सुरक्षा से ही विकसित बनेगा भारत

पिछले दिनों गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन हुआ। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भारत ने जहां निवेश के अवसर पेश किए, वहीं अपनी ऊर्जा नवाचार क्षमता से भी विश्व जगत का ध्यान आकर्षित किया। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति को टिकाऊ बनाने के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी हासिल करनी होगी। उम्मीद है भारत ऊर्जा सप्ताह में लिए गए फैसले इसमें मददगार बनेंगे

वैश्विक ऊर्जा सहयोग का केंद्र बनता भारत। एएनआइ

भारत समेत वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में इन दिनों तेजी से बदलाव हो रहा है। भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति को टिकाऊ बनाना होगा। इसे देखते हुए देश जीवाश्म ईंधन के नवीकरणीय विकल्पों से ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। इसी कड़ी में गत छह से नौ फरवरी तक गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह-2024 के दूसरे संस्करण में भारत के ऊर्जा विविधिकरण को दुनिया ने देखा। 17 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की मौजूदगी में भारत ने जहां 67 अरब डालर से जुड़े निवेश के अवसर पेश किए, वहीं अपनी ऊर्जा नवाचार क्षमता से भी विश्व जगत का ध्यान आकर्षित किया। रूस की रोसनेफ्ट, सऊदी अरब की अरामको, कतर गैस, शेवरान जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की इस ऊर्जामयी यात्रा में अभी भागीदार हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान एशियाई देशों के ऊर्जा मंत्रियों का नौवां सम्मेलन भी आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के सदस्य देशों ने कार्बन कैप्चर स्टोरेज और हाइड्रोजन तकनीक की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। उम्मीद है ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 35 हजार वैश्विक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ भारत ऊर्जा सप्ताह देश की ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने का एक अहम मंच साबित होगा।

ऊर्जा तकनीक का अगुआ बनता भारत : भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान कई दिग्गज कंपनियों ने अपने नवाचार प्रस्तुत किए। भारतीय तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बीपीसीएल) ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्वदेशी अल्कलाइन (क्षारीय) इलेक्ट्रोलाइजर पेश किया। यह दुनिया में सबसे सस्ता और लागत सक्षम इलेक्ट्रोलाइजर है। भाभा परमाणु शोध संस्थान (बीएआरसी) के सहयोग से इसका प्रोटोटाइप माडल तैयार कर लिया गया है। यह क्षारीय जल का उपयोग करता है। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से क्षारीय जल से हाइड्रोजन पैदा किया जाता है। यह तकनीक क्षारीय वातावरण में हाइड्रोजन सेल की दक्षता को बढ़ाती है। इस प्रौद्योगिकी से उद्योगों के जरिये बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन संभव है। भारत ने वर्ष 2030 तक पांच मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

नवाचार से टलेंगे ऊर्जा परियोजनाओं में हादसे : भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज तेल एवं गैस कंपनी ओएनजीसी द्वारा तैयार समुद्री सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। समुद्र में तेल एवं गैस परियोजनाएं सबसे जटिल अवसंरचना होती हैं। समुद्र में तेल और गैस उत्खनन तथा परिशोधन के दौरान जोखिम का स्तर बहुत अधिक होता है। यहां मानव निर्मित हादसों के अलावा चक्रवात और मौसम में बदलाव का खतरा बना रहता है। ऐसे में मानव जनित तथा प्राकृतिक हादसों का प्रभाव कम करने के लिए ओएनजीसी ने समुद्री सर्वाइवल सेंटर स्थापित किया है। इससे तेल एवं गैस के उत्खनन में लगे मानव संसाधन को समुद्र में उच्चस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अक्सर समुद्र में चक्रवात एवं तेज हवाओं से हेलिकाप्टर क्रैश की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बचाने के लिए समुद्री सर्वाइवल सेंटर काम आएगा। इससे संवेदनशील ऊर्जा परियोजनाओं में कार्यरत मानव संसाधन में आत्मविश्वास का संचार होगा। यह केंद्र हर साल 15 हजार लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। इससे भारत की दक्षिण एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी भी मजबूत होगी। उल्लेखनीय है कि देश में तेल एवं गैस का 70 प्रतिशत उत्खनन अपतटीय होता है।

नई ऊर्जा साझेदारियों को प्रोत्साहन : वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च किए जा रहे 11 लाख करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र को जा रहा है। भारत की मौजूदा आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत से अधिक है। इसे और गति देने के लिए आगे हमें ऊर्जा क्षेत्र में नई साझेदारियां करनी होंगी। भारत ऊर्जा सप्ताह की एक बड़ी उपलब्धि कतर एनर्जी जैसी कंपनी के साथ अगले 20 साल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात के लिए 78 अरब डालर का समझौता है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयातक कंपनी पेट्रोनेट लिमिटेड ने देश में बिजली, उर्वरक और सीएनजी की मांग की पूर्ति के लिए कतर से प्रतिवर्ष 75 लाख टन गैस खरीदने का समझौता किया है। आशा है भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में कतर के साथ यह द्विपक्षीय साझेदारी मील का पत्थर साबित होगी। खास बात यह है कि इस समझौते से भारत को वर्तमान भाव पर 0.8 डालर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बचत होगी। इससे 2048 तक भारत को छह अरब डालर का लाभ होगा। इससे भारत को होने वाले एलएनजी आयात में कतर की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 35 प्रतिशत हो जाएगी। प्राकृतिक गैस के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच पहली बार 31 जुलाई, 1999 को समझौता हुआ था। यह 2028 तक के लिए ही था। कतर के साथ 2028 से लागू होने वाला नया एलएनजी समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाड़ी देश कतर अमेरिका के बाद एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने एलएनजी उत्पादन की क्षमता को 2027 तक 7.7 करोड़ टन से बढ़ाकर 12.6 करोड़ टन प्रतिवर्ष करने की योजना बनाई है। हमारी ऊर्जा की जरूरतों में अभी प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी छह प्रतिशत है। इसे इस दशक के अंत तक 15 प्रतिशत के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य है।

केंद्र सरकार देश की रिफाइनरी क्षमता को 25.4 करोड़ टन वार्षिक से बढ़ाकर 45 करोड़ टन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत अब अपनी तेल जरूरतों के लिए सिर्फ खाड़ी के देशों पर ही निर्भर नहीं है। भारत ने तेल एवं प्राकृतिक गैस की खरीद में लागत और घरेलू हितों को वरीयता दी है। पिछले वर्ष भारत ने सबसे अधिक कच्चे तेल की खरीदारी रूस से की। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश अपने पुराने सहयोगी रूस से प्रतिदिन 16.6 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद कर रहा है। इससे पहले 2022 में यह आंकड़ा 6.51 लाख बैरल प्रतिदिन था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का न सिर्फ बड़ा केंद्र बना, बल्कि यूरोप को सस्ती दरों पर परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर ऊर्जा क्षेत्र के बड़े बाजार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। इससे एक ओर पेट्रोलियम क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, वहीं ओपेक देशों के दबाव से भी हमें मुक्ति मिल रही है। अप्रैल से दिसंबर 2023 तक भारत को कच्चे तेल के आयात में ओपेक देशों की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत के स्तर पर आ गई, जबकि इससे पहले यह 65 प्रतिशत के स्तर पर थी। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के अवसर भी यूरोपीय साझेदारों के समक्ष प्रदर्शित किए गए।

ऊर्जा विविधीकरण की सुगम होती राह

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस के हम चौथे बड़े निर्यातक हैं। देश में प्राथमिक ऊर्जा मांग वर्ष 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। देश में पिछले पांच साल में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 162 प्रतिशत बढ़ा है। हमारी ऊर्जा जरूरतों में 158.12 गीगावाट (लगभग 40 प्रतिशत) हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की है। 2035 तक इसे 450 गीगावाट के स्तर पर ले जाना है। ऐसे में सौर ऊर्जा के साथ ही हमें ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनाल और कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं में अधिक निवेश करना होगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में भारत एथेनाल बाजार में कनाडा और चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। एथेनाल मिश्रित ई-20 ईंधन 9,700 रिटेल केंद्रों पर मिल रहा है। भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य तय किया है, वह ऊर्जा सुरक्षा के साथ बिना अड़चन के हासिल किया जा सके, ऐसे में ऊर्जा विविधिकरण की नीति सबसे कारगर होगी। यही वजह है कि भारत तेल, प्राकृतिक गैस तथा कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन के साथ ही अक्षय ऊर्जा से जुड़ी तकनीक और अवसंरचना के विकास पर भी जोर दे रहा है।

भारत ऊर्जा सप्ताह में भारतीय कंपनियों द्वारा ऊर्जा भंडारण, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट ग्रिड, आधुनिक कोयला और कार्बन भंडारण तकनीक से जुड़े नवाचार पेश किए गए। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन (आइईएसए) द्वारा भारत बैट्री आपूर्ति शृंखला परिषद का गठन पहले ही किया जा चुका है। आधुनिक रसायन सेल (एसीसी बैट्री) के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इसे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना से संबद्ध किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के असीमित स्रोत सौर ऊर्जा की क्षमता को पहचानते हुए प्रधानमंत्री ने गत दिनों पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की। इससे एक करोड़ परिवार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। घरों में बनने वाली अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने का काम भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में देश का पहला आनग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार है। यह बैट्री ऊर्जा भंडारण क्षमता पर आधारित है। आनग्रिड सोलर सिस्टम की मदद से तैयार सौर बिजली को सीधे परंपरागत ग्रिड में पहुंचाया जा सकता है। इस प्रणाली में फोटोवोल्टिक पैनल, इनवर्टर, विद्युत केबल और ग्रिड कनेक्शन का उपयोग होता है। इससे तैयार बिजली अधिशेष होने पर संग्रहित की जा सकती है। इससे किसान और साधारण उपभोक्ता सौर ऊर्जा के लिए प्रेरित होंगे।

-अरविंद कुमार मिश्रा

खरी-खरी

कोई लौटा दे, मेरे बीते हुए दिन

धर्मेंद्र जोशी

यूं तो प्रेम बाबू अपने परिणय बंधन की रजत जयंती मना चुके हैं, मगर साल में जब फरवरी के महीने में प्रणय दिवस आता है तो वह स्मृतियों में चले जाते हैं। हालाकि उनके समय में रोज डे, चाकलेट डे, हग डे और वैलेंटाइन डे जैसे पाश्चात्य देशों के चोंचले तो नहीं थे, मगर प्रेम-निवेदन, संयोग-वियोग और प्रेम पर पहरेदारी जैसे शाश्वत बंधन तो अस्तित्व में थे ही। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उन्हें घर की जिम्मेदारी का अहसास तो बचपन से ही करवा दिया गया था, लेकिन उनमें कब प्रेम का प्रस्फुटन हो गया, पता ही नहीं चला। संचार साधनों के अत्यंत अभाव के बावजूद प्रेम बाबू के पिताजी को इसका पता लग गया। इसके बाद के घटनाक्रम को तो हर वह व्यक्ति जानता है, जिसने अपने जीवन में प्रेम किया हो। सर्वप्रथम तो पिताजी ने अपनी वंशावली का गुणगान किया। उसके पश्चात पढ़ाई पूरी करने की हिदायत दी। मगर प्रेम कब बंदिशों में रहा। प्रेम ने तो दरिया और तूफानों की भी कभी परवाह नहीं की। प्रेम रूप-रंग, ऊंच-नीच, अमीरी-गरीबी और सरहदों से भी परे रहा है।

तब के प्रेम बाबू अब प्रौढ़ हो गए हैं। बालों से झांकती सफेद चांदी उनके अनुभव को प्रतिबिंबित कर रही है। अपने युवा दिनों के प्रेम की तुलना आज के समय के प्रेम से करते हैं तो बहुत अंतर पाते हैं। उन दिनों का रूहानी प्रेम अब देह पर आकर ठहर गया है। सबकुछ न्योछावर करने की भावना अब निज हित में तब्दील हो गई है। रूमानियत का स्थान अब उन्माद ने ले लिया है। प्रेम की खुशबू ने एक अजीब उकताहट का रूप ले लिया है।

बहरहाल प्रेम बाबू स्मृतियों में खोए हुए थे, इतने में एक स्वर सुनाई दिया। कब तक धूप में बैठकर आईने में खुद को निहारते रहोगे? गैस का नंबर लगा दो, पानी की टंकी अंतिम सांसे ले रही है, घर में कोई सब्जी नहीं है और राशन का तीन दिन से कह रही हूं, अब तो ले आओ। प्रेम बाबू स्मृतियों के सुहाने सफर से वास्तविकता के धरातल पर आ गए। चप्पल पहनकर 'कोई लौटा दे, मेरे बीते हुए दिन' गीत को गुनगुनाते हुए बाजार की ओर चल दिए।

पोस्ट

जिस-जिस राजनीतिक दल के रणनीतिकार यूट्यूबर्स से 'ज्ञान' लेंगे, उनका रसातल में जाना तय है।
परवेज अहमद@parvezahmadj

दिल्ली में आप कांग्रेस को लोकसभा की केवल एक सीट की पेशकश कर रही है। अब आप भी आइएनडीआइए से बाहर समझिए। आशुतोष@ashutosh83B

एमएसपी देश के किसानों के हित में नहीं है। उन्हें हमेशा सरकार की कृपा पर रखने, गरीब बनाए रखने और किसान नेताओं की दुकान चलाने का एक जरिया भर है।
हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

भीड़तंत्र के सहारे लोकतंत्र के दमन के तरीकों से कड़ाई से निपटना चाहिए। बाबा साहेब आंबेडकर तो गांधी जी के आमरण अनशन के भी आलोचक थे।
रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

राहुल गांधी कभी पुरानी पेंशन का वादा करते हैं तो कभी ओबीसी जनगणना का। कभी एमएसपी का। बिना कोई सोच विचार हर दिन नया वादा। यह भी देंगे, वह भी देंगे, बस एक बार ले आओ हमको। ऐसे कैसे चलेगा?
सौरव शर्मा@journosaurav

इन्द्रप्रीत सिंह
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

पंजाब डायरी

क्या कोई बीच का रास्ता नहीं बचा?

सोमवार को रात साढ़े ग्यारह बजे तक जब पंजाब के कुछ किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत चलती रही तो लगा कि आज कोई न कोई फैसला होकर ही रहेगा। लगा कि 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने का मामला हो या किसानों के लिए भी पेंशन योजना लाने या फिर उन पर चढ़े कर्ज को माफ करने का विषय हो, इन सभी मुद्दों पर कोई न कोई बीच का रास्ता निकालकर दोनों पक्ष सहमति बन लेंगे। इंटेलिजेंस के कुछ कर्मचारी तो यह भी कहते रहे कि चूंकि बैठक लंबी चल रही है इसलिए सहमति बनती दिख रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गए होते, लेकिन जब साढ़े पांच घंटे बाद बैठक किसी नतीजे पर पहुंचे बिना ही समाप्त हो गई तो पता चला कि कोई भी पक्ष अपने रुख से टस से मस होने को राजी नहीं था। बैठक में मौजूदा कुछ अधिकारियों का कहना है कि दरअसल दोनों पक्ष एक-दूसरे के पाले में गेंद डालना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री चाहते थे कि किसान संगठन बैठक का बहिष्कार करके चले जाएं। दूसरी ओर किसान संगठन चाहते थे कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी एवं अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार कोई कमेटी बनाना चाहती है तो उन्हें कम से कम यह लिखित में आश्वासन दे कि वह कमेटी एमएसपी की गारंटी पर बिल लाने संबंधी काम करेगी।

अब सवाल यह है कि क्या इस गतिरोध को खत्म करने के लिए बीच का कोई रास्ता हो सकता था? फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून की मांग कर रहे किसान संगठन पंजाब के हैं। मालूम हो कि पंजाब में पहले से ही दो फसलों-गेहूं और धान पर एमएसपी लागू है। साथ ही खरीद की गारंटी भी है। जबकि दो अन्य फसलें-गन्ना और कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं अधिक दाम में बिकती हैं। पांचवीं फसल सरसों की है। यह भी पिछले कुछ वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक में बिक रही है। केवल मक्का की फसल ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिक रही है। पंजाब के किसानों ने दालों की खेती करनी अब बंद कर दी है। इसी तरह हरियाणा ने भी 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रखा है। वहां अगर इससे कम मूल्य पर फसलें बिकती हैं तो राज्य सरकार भावांतर योजना से उस कमी को पूरी कर देती है। सवाल है कि फिर देश के वे किसान जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, वे केंद्र सरकार से इसकी मांग क्यों नहीं करते?

वैसे सभी फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना कोई मुश्किल काम नहीं है। कर्नाटक के किसान आयोग ने साल 2014 में इसकी राह दिखाई हुई है। वहां के किसान आयोग ने राज्य की मंडियों में बिकने वाली फसलों पर 1.5 प्रतिशत टैक्स लगाकर एक कोष बनाया है। उसने अपने राज्य के सभी किसानों से कह रखा है कि वे जब भी अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में ले जाएं तो पोर्टल पर उसकी रेट जरूर जांच लें। अगर उन्हें खुले बाजार में अपनी फसल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा मिल रही है तो वे व्यापारियों को बेच दें और अगर वहां कम दाम मिल रहा है तो राज्य सरकार उनकी सभी फसल खरीदेगी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने फसलों को खरीदकर उन्हें अपने विभिन्न विभागों जैसे कि जेल, थाने, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल आदि में उपलब्ध करवाती है। यहां सरकार की ओर से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इससे राज्य सरकार को किसानों से खरीदी गई फसलों को खपाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। यह माडल देश भर में लागू करने में क्या दिक्कत है?

पंजाब में इस साल किन्नू जैसे फल की पैदावार बहुत ज्यादा हुई है। उचित दाम न मिलने के कारण किसान परेशान हैं। उन्होंने फाजिल्का के बाजारों में किन्नू की ढेर लगा दी है। दूसरी ओर मिड डे मील जैसी योजना में राज्य सरकार छात्रों को पंजाब का किन्नू देने के बजाय महाराष्ट्र से केला खरीदकर दे रही है। अगर पंजाब में मिड डे मील में बच्चों को किन्नू दिया जाता तो किसानों को भी उसकी अच्छी कीमत मिल जाती। राज्य में अभी 19 लाख बच्चे मिड डे मील योजना में पंजीकृत हैं। इस प्रकार हर महीने लाखों किन्नू बच्चों को मिल सकते थे। इसी तरह फसलों के लिए भी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। जाहिर है अगर प्रतिबद्धता दिखाई जाए तो फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना संभव है।

बातचीत से ही निकलेगा कृषि समस्या का समाधान। फाइल

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का मूल कारण गांधी परिवार की रीति-नीति है?

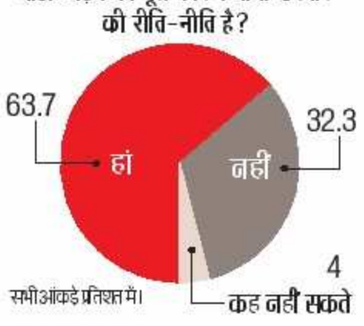

समी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या सरकार के लिए समस्त अन्न की खरीदारी करना संभव है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

खेला होता जा रहा प्रतिदिन उनके साथ,
जो ऊंचा कर घूमते कांग्रेस का हाथ।
कांग्रेस का हाथ होय कमजोर निरंतर,
मार रहा है कौन न जाने उस पर मंतर।
राहुल जी ले घूम रहे हैं उधर झमेला,
होता जाए खत्म इधर उनका सब खेला!
- ओमप्रकाश तिवारी

महाराष्ट्र डायरी

जारी है राजनीतिक 'खेला'

ओमप्रकाश तिवारी
ब्यूरो प्रमुख, मुंबई

महाराष्ट्र के भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों में अब तक सिर्फ कांग्रेस ही टूट से बची हुई थी। अब उसमें भी टूट की शुरुआत हो गई है। अशोक चह्वाण के भाजपा में आने के बाद लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस कितना टूटती है और कितना बचती है, बस यह देखना बाकी है। वर्ष 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दो भाजपा विरोधी दलों कांग्रेस एवं राकांपा, तथा भाजपा के एक मित्र पक्ष शिवसेना ने मिलकर गजब का 'खेला' किया था। जबकि शिवसेना ने तो वह विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर ही लड़ा था। तब तीनों दलों ने मिलकर सत्ता के मुहाने पर खड़ी भाजपा के पांव तले का 'लाल कालीन' खींच लिया था। अचंभित भाजपा लंबे समय तक समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि वह उक्त तीनों दलों की अपेक्षा लगभग दोगुनी सीटें जीतकर आई थी। उसके नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस दावे के साथ चुनाव प्रचार किया था कि 'मी पुनः येईल' (मैं पुनः आऊंगा), लेकिन तब उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस का यह नारा भी मजाक बनकर रह गया था। शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा को मिलाकर बनाई गई महाविकास आघाड़ी के मुख्य शिल्पकार शरद पवार थे। उन्हीं ने सोनिया गांधी से संपर्क कर उन्हें शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए राजी किया था।

राज्य में हुई इस राजनीति से गहरी चोट खाए देवेंद्र फडणवीस के पास उस समय शांति से सबकुछ देखते रहने और सही मौके का इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। सही मौका आया करीब ढाई वर्ष बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के दौरान। 10 जून, 2022 को महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटों के लिए हुए चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को पटखनी देकर अपने विरोधियों को भी अपनी रणनीति का कायल बना दिया था। उस समय मिली हार से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भौचक्के रह गए थे। जिन छोटे दलों एवं निर्दलियों के भरोसे वह अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत का ख्वाब पाले बैठे थे, वे सब विरोधी दल भाजपा के खेमे में जा चुके थे। यही नहीं, भाजपा के तीसरे उम्मीदवार धनंजय महाडिक को मिले मतों का वजन शिवसेना के पहले उम्मीदवार संजय राउत से भी ज्यादा था। शिवसेना मानकर बैठी थी कि उसके सत्ता में रहने के कारण छोटे दल एवं निर्दलीय उससे दूर जा ही नहीं सकते। भाजपा को मिली जीत पर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को भी कहना पड़ा था कि यह देवेंद्र फडणवीस की कुशल रणनीति की जीत है।

राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई महाविकास आघाड़ी की मात का सिलसिला ठीक 10 दिन बाद हुए विधान परिषद चुनावों में भी दिखा। 20 जून, 2022 को 10 सीटों के लिए हुए विधान परिषद के चुनाव में भाजपा ने अपनी क्षमता से अधिक पांच उम्मीदवार खड़े किए थे, और उसके पांचों उम्मीदवार विजयी रहे। तब महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर अपना दबदबा एवं रणनीतिक कौशल दिखाने में कामयाब रहे। महाविकास आघाड़ी को विधान परिषद के चुनाव में लगा यह झटका अंतिम नहीं था, बल्कि यह तो झटकों की शृंखला की शुरुआत भर थी। बड़ा झटका तो अगले दिन लगा, जब सुबह होते ही शिवसेना के एक कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे अपने कुछ साथी विधायकों के साथ सूरत जा पहुंचे। अगले कुछ ही दिनों में उनके साथ विधायकों का समर्थन बढ़ता गया। वह सूरत से गुवाहाटी गए और कुछ दिनों बाद शिवसेना के 39 अन्य विधायकों के साथ बगावत कर अपना अलग गुट बनाकर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। अब बारी थी उद्धव के पैरों तले से जमीन खिसकने की। अब तक तो उद्धव के हाथ से पार्टी और उसका चुनाव चिह्न भी जा चुका है।

हालांकि उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभानेवाले शरद पवार को सबक सिखाना अभी बाकी था। फडणवीस को यह मौका मिला दो जुलाई, 2023 को। जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नौ साथी विधायकों के साथ शिंदे-फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दिए। अब कुछ ही दिनों पहले आए चुनाव आयोग के निर्णय के बाद शरद पवार के हाथ से उन्हीं की स्थापित राकांपा और उसका चुनाव चिह्न चला गया है। कांग्रेस अब तक इस टूट-फूट से अछूती थी। कांग्रेस इसे अपनी ताकत मान रही थी। इसी ताकत के भरोसे पिछले वर्ष निकली राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' का महाराष्ट्र में प्रवेश अशोक चह्वाण के गृह क्षेत्र नांदेड़ से हुआ और उसका जोरदार स्वागत भी हुआ था। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता रहे अशोक चह्वाण ही अब भाजपा में आ चुके हैं। उनसे पहले पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट और बाबा सिद्दीकी राकांपा अजीत गुट में जा चुके हैं। टूट का यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता रहे अशोक चह्वाण (दाएं) ने थामा भाजपा का दामन। प्रेट्र

****

For More Newspapers And Magazines Join Paid Group Whatsapp To 8969469464

हिन्दुस्तान 1936 सत्य · सार्थक · सदैव

किसान आंदोलन

एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर केंद्र और किसान संगठनों के बीच टकराव की स्थिति के मद्देनजर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उचित ही कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए और बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय के तौर पर ही हो। निस्संदेह, देश के अन्नदाताओं के विरुद्ध बल प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का अभीष्ट नहीं हो सकता, न होना चाहिए, मगर उसके ऊपर यह जिम्मेदारी भी आयद है कि वह ऐसी किसी अराजकता या अव्यवस्था की मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती, जो व्यापक नागरिक समाज की जिंदगी को परेशानी में डालती हो। 12 फरवरी की रात केंद्र सरकार व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बातचीत के विफल रहने के बाद यह अंदेशा था कि 13 को प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे और मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर जो परिस्थिति पैदा हुई, उसने इसे सही साबित किया। दिल्ली के सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवागमन पर काफी असर पड़ा है। सर्विस लेन के बंद होने से इन क्षेत्रों में जाम की स्थिति बन गई है और लोगों को काफी दूर-दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है।

साल 2020 में जब तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध पहली बार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देने बैठ गए थे, तब भी स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हुई थी, मगर उस अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण धरने को आम लोगों की सहानुभूति हासिल थी, क्योंकि देश का एक बड़ा जन-समुदाय खेती-किसानी से जुड़ा है, या जो लोग कृषि कर्म से अलग होकर शहरों-महानगरों में आ बसे हैं, उनकी पुरानी पीढ़ियों में अब भी इस वर्ग के प्रति गहरी हमदर्दी कायम है। मगर 26 जनवरी, 2021 को लाल किले में जैसी अशोभनीय घटना घटी, उसने उस आंदोलन के प्रति आम लोगों का नजरिया बदल दिया था। हालांकि, किसानों और नागरिक भावनाओं का सम्मान करते हुए बाद में सरकार ने उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया था और तब केंद्र व किसानों के बीच विश्वास बहाली का आधार बना था।

प्रदर्शनकारी किसानों को नहीं भूलना चाहिए कि आम नागरिकों को परेशानी में डालकर वे न तो आंदोलन को नैतिक धार दे सकते हैं, न ही इसके लिए जन-समर्थन जुटा सकते हैं।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जब-जब चुनाव करीब आते हैं, तब सरकार से सहूलियत चाहने वाले वर्ग और कर्मचारी संगठन आंदोलनों का सहारा लेते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यदि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ-साथ अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निबाह कर रहे हों, मगर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और विधि-व्यवस्था को बाधित करने की किसी भी कार्रवाई की कतई हिमायत नहीं की जा सकती। प्रदर्शनकारी किसानों को नहीं भूलना चाहिए कि आम नागरिकों को परेशानी में डालकर वे न तो अपने आंदोलन को नैतिक धार दे सकते हैं और न ही इसके लिए व्यापक समर्थन जुटा सकते हैं। निस्संदेह, सरकार के आगे गंभीर चुनौती है। इस चुनावी समय में वह विशाल किसान समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, तब तो और, जब उसकी मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने की सूरत में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, एमएसपी कानून की गारंटी देने का दांव चल दिया है। मुश्किल यह है कि सरकार के पास बहुत वक्त भी नहीं है। उसे प्रतीकों की सियासत से बढ़कर किसानों को आश्वस्त करना ही होगा, क्योंकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश शांत है, अगर वहां के किसानों ने कूच किया, तो इस आंदोलन को शांत करना और दुरूह हो जाएगा।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 14 फरवरी, 1948

नेहरू के दर्शन को उमड़ी भीड़

आनन्द, १३ फरवरी। आज प्रातःकाल अहमदाबाद से आनन्द तक ५० मील तक रेलवे लाइन के सहारे गुजरात के ग्रामीण लोगों की विशाल भीड़ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दर्शन के लिए खड़ी थी। नेहरूजी यहां वल्लभनगर की आधारशिला रखने के लिए एक विशेष रेलगाड़ी से आये थे। यह नगर उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय नगर के रूप में बसाया जा रहा है। नये नगर का स्थान रामसद गांव की सीमा पर है जो सरदार पटेल का जन्मस्थान है। इस प्रस्तावित नगर के समीप कुछ कालेज और छात्रावास बस रहे हैं, कुछ कालेज और छात्रावास चल भी रहे हैं। इनकी आधारशिला गत वर्ष रखी गई थी।

नगर की आधारशिला रखने के बाद भाषण देते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा- ''यह नगर और इसके आसपास बनी हुई संस्था इस बात का प्रमाण देती है कि रचनात्मक उद्योग से सब कुछ किया जा सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस नगर का नाम भारतमाता के प्रख्यात पुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। किन्तु उन्हें तो समस्त भारत अपना मानता है और वे समस्त भारत के हैं भी। ...चूंकि यह स्थान सरदार का जन्मस्थान है, इसलिए वह इस सम्मान का पात्र है। गुजरात आने की मेरी इच्छा बहुत पहिले से थी। किन्तु मुझे उसका अवसर नहीं मिला। अब मैं यहां तीर्थयात्रा करने आया हूं। मुझे बड़ा दुःख है कि गुजरात में अकाल की अवस्थायें हैं। मैं अपनी ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि केन्द्रीय सरकार आपके कष्ट दूर करने के प्रयत्न करेगी। किन्तु साथ ही लोगों को अपने प्रयत्न में भी कसर न रखनी चाहिए और वर्तमान अवस्थाओं में जितना पैदा किया जा सकता है, उतना उन्हें पैदा करना चाहिए।''

देश की खाद्य-स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नदियों के बांध बनाने की योजनायें पूरी नहीं होती हैं, तब तक देश में खाद्य-पदार्थों की कमी रहेगी। मैं भी इस बारे में लोगों को शक्ति भर प्रयत्न करने और यदि आवश्यकता हो तो खाने-पीने की अन्य चीजों से अन्न की कमी पूरी करने की सलाह देता हूं। हैदराबाद से आनन्द तक लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गये थे और दोनों ओर तारों पर लटक गये थे।

दिल्ली की दहलीज पर फिर अन्नदाता

कहा जाता है कि 14 फीसदी किसान ही एमएसपी का लाभ लेते हैं, शेष 86 फीसदी बाजार में अपनी फसल बेचते हैं। गणित इतना ही सरल होता, तो किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों मांगते?

यहां स्कैन करें

देविंदर शर्मा | कृषि विशेषज्ञ

दिल्ली के दर पर किसान फिर जुट आए हैं। 2020-21 के आंदोलन से सबक लेते हुए इस बार राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर जबर्दस्त बंदोबस्ती की गई है। भारी बाड़ेबंदी के साथ-साथ पुलिस बल को विशेष तौर पर तैयार रखा गया है। फिर भी, मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर दिन भर तनातनी होती रही। सवाल है, आखिर क्यों किसान बार-बार दिल्ली आने को मजबूर होते हैं?

अगर किसानों की समस्याओं का उचित समाधान हो जाए, तो भला वे क्यों अपनी खेती-किसानी छोड़कर आंदोलन करेंगे? उन्हें क्यों शौक होगा कि वे दिल्ली की सड़कों पर सर्दी, गरमी या बरसात झेलें? पिछले आंदोलन के दौरान उन्होंने किसी न किसी मजबूरी में ही महीनों तक अपने गांव-घर से दूर तंबुओं में दिन गुजारे। आखिर इस बार की मजबूरी क्या है? वास्तव में, वे अपनी तीन मुख्य मांगों पर दिल्ली के सत्ता-सदन की मुहर चाहते हैं। पहली मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी मिले। दूसरी मांग, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी तय हो, और तीसरी, जो कर्ज उन पर है, उसको माफ किया जाए। इसके अतिरिक्त, पुराने आंदोलनों में दर्ज हुए मुकदमों की वापसी हो, शहीद किसानों को मुआवजा जैसी कुछ अन्य मांगें भी इस बार शामिल की गई हैं।

ये कोई गैर-वाजिब मांगें तो नहीं हैं। पिछले 15 वर्षों में उद्योग जगत के लगभग 15 लाख करोड़ रुपये माफ किए गए हैं, जबकि उद्योगपतियों को हमने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते नहीं देखा है। इसके उलट, किसान जब कभी अपनी आवाज उठाते हैं, तो बदले में उन्हें लाठियां- गोलियां मिलती हैं। मंगलवार को ही किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दिल्ली सीमा को इस कदर सील किया गया है, मानो अब वहां बारूदी सुरंग बिछाना ही शेष रह गया है। जब तक समाज के ऊपरी और निचली तबके के बीच यह विभेद बना रहेगा, तब तक दिल्ली आने के सिवाय किसानों के पास कोई

दूसरा रास्ता शायद ही होगा!

आरोप यह भी है कि चुनावी साल में किसान दबाव की राजनीति कर रहे हैं? अव्वल तो किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं, क्योंकि यह उनके जीवन-मृत्यु से जुड़ा मसला है। साल 2020-21 में क्या कोई चुनाव था, जो महीनों तक किसानों ने दिल्ली में डेरा डाले रखा? फिर भी, यदि यह किसी को राजनीति लगती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। खेती-किसानी पर निर्भर देश की यह 50 फीसदी आबादी अपने हितों के लिए राजनीति क्यों न करे? क्या यह अधिकार सिर्फ राजनेताओं के पास है, जो पुरस्कारों के नामों पर भी राजनीतिक रोटी सेंक लेते हैं? हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा कि एसी कमरों में बैठने वाले लोगों की तुलना में किसान कम समझदार होते हैं।

किसानों की तकलीफ का एक हालिया उदाहरण आपको बताता हूं। पिछले दिनों पंजाब के किसानों ने किन्नू की करीब 75 ट्रॉलियों को ट्रैक्टर से रौंद दिया। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि शहरी इलाकों में भले ही यह फल 100 रुपये में तीन किलो मिलता हो, पर इसे उपजाने वाले हाथों को इसकी कीमत सिर्फ पांच रुपये प्रति किलो मिल रही थी। एक तरफ कहा जाता है कि पंजाब में किसानों को अपनी फसलों में विविधता लानी चाहिए, क्योंकि एकरूप फसल से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, जब किसान विविधता लाते हैं, तो उन्हें अपनी फसलों को बर्बाद करना पड़ता है। इस तरह के तमाम उदाहरण देश भर में देखे जा सकते हैं। आयात-निर्यात संबंधी नीतियों का नुकसान भी किसानों को होता है। ऐसे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी मांगना भला कैसे गलत है? मगर इसकी मांग करते हुए वे दिल्ली आते हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी को एक किले में बदल दिया जाता है, मानो वे कोई राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं।

उनकी मांगों को न मानने की पीछे एक खास वजह है। असल में, हमारा आर्थिक ढांचा किसानों को जान-बूझकर गरीब रखने का हिमायती है। इसमें जिस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर रिजर्व बैंक महंगाई नियंत्रित करने की कवायद करता है, उसमें फसलोपज की कीमतों को लेकर अतिरिक्त संजीदगी दिखाई जाती है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 45 फीसदी हिस्सा कृषि-उपज का है। यही कारण है कि फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ने के साथ ही महंगाई बढ़ने का राग अलापा जाने लगता है। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास पर होने वाले खर्च की गणना नहीं की जाती, जबकि इलाज में, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में या शहरों में किसी छत के नीचे रहने में कितने पैसे खर्च होते हैं, यह छिपा रहस्य नहीं है। तर्क दिया जाता है कि फल व सब्जी सभी खाते हैं, इसलिए इसकी महंगाई लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास लोगों से नहीं जुड़ा है? यह समझ से परे है कि हम दुनिया की शीर्ष पांच आर्थिक ताकतों में शामिल हैं, लेकिन फल और सब्जियों के दाम बढ़ने मात्र से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है।

हमारे नियामक यह भी कहते हैं कि जब बाजार खुला है, तब किसानों को एमएसपी की मांग नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है, देश के 14 फीसदी किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेते हैं, शेष 86 फीसदी तो बाजार में अपनी फसल बेचते हैं। अगर बाजार का गणित इतना सरल होता, तो भला क्यों किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे होते? साफ है, संसद के बयान और सड़क के हालात में अंतर है।

देखा जाए, तो किसानों को फसलों के लिए मिलने वाले उचित दाम देश के लिए अच्छे हैं। जब उनके पास पैसे आएंगे, वे खरीदारी तेज करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और देश की तरक्की होगी। यह साधारण फॉर्मूला भी हम समझना नहीं चाहते। हम पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं, जबकि वहां किसानों को लेकर अलग रुख है। अपने यहां तो अब कोई किसान ही नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती-किसानी करे।

किसानों की समस्या का समाधान सिर्फ केंद्र के पास है। महाराष्ट्र जैसे राज्य अपने तईं 6,000 रुपये की सालाना मदद किसानों की करते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। किसानों को खैरात नहीं, अपना हक चाहिए, जो उनकी मांगों को मानने से ही मिल सकता है। मगर क्या इस बार वे सफल होंगे? फिलहाल, इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

गृह, मग, वन में आया वसंत सुलगा फागुन का सूनापन

यहां स्कैन करें

प्रयाग शुक्ल | कवि और कला मर्मज्ञ

हवा हूं, हवा मैं/ वसंती हवा हूं।/ सुनो बात मेरी-/ अनोखी हवा हूं।/ बड़ी बावली हूं,/ बड़ी मस्तमौला।/ नहीं कुछ फिकर है,/ बड़ी ही निडर हूं।/ जिधर चाहती हूं,/ उधर घूमती हूं,/ मुसाफिर अजब हूं।

कवि केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता अक्सर याद आ जाती है, पर वसंत पंचमी के दिन तो अवश्य याद आती है। ऐसी मदमस्त हवा के साथ ही रंग भी याद आते हैं और फिर याद आता है वह प्रसिद्ध गीत- *मेरा रंग दे बसंती चोला...*। वसंत प्रेम, शौर्य और उमंग की भी ऋतु है। यह अकारण नहीं है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवयित्री ने *जलियांवाला बाग में वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत* शीर्षक से कविताएं लिखी हैं।

यह माघ शुक्ल पंचमी का जो दिन है, यह वसंत पंचमी का दिन है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी याद आती है। परंपरा रही है हमारे देश में, जिसे पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जा रहा है, तो वसंत पंचमी से श्रीगणेश किया जा सकता है। सोचिए कि यह परंपरा क्यों बनी? वसंत में कुछ ऐसा है कि अक्षर तो है ही, इसमें अमरता का भी एक बोध है। अनेक राज्यों में विद्यालयों व शिक्षा संस्थानों में सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। इस ऋतु में शिक्षा और ज्ञान का महत्व भी ध्यान में आता है, जब महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां गूंज उठती हैं - *वर दे वीणावादिनी वर दे।*

यह ऋतु ही अपने आप में अनुष्ठान है, हममें से कोई भूल भी जाए, तो प्रकृति इस अनुष्ठान को मनाने के तमाम यत्न स्वतः करने लगती है।

अद्भुत सौंदर्य से सराबोर अनंत वसंत आता नहीं है, अवतरित होता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से थोड़ा अंतर आया है। मैं घूमता रहता हूं, मुझे महसूस होता है कि अनेक जगहों पर अभी भी कड़ाके की सर्दी है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। वसंत पंचमी पर सुंदर धूप खिल उठती थी और उसका ताप शरीर में स्फूर्ति ला देता था। हालांकि, अभी भी कुछ जगहों पर अच्छी धूप खिली है और उसके साथ ही फगुनाहट का भी अनुभव होने लगा है। अर्थात वसंत पंचमी से फागुन अर्थात होली की भी आहट हो गई है। अनेक स्थानों पर वसंत पंचमी से ही रंगोत्सव की शुरुआत हो जाती है।

वसंतोत्सव को कलाओं से भी जोड़ा जाता है, यह शांतिनिकेतन में भी धूमधाम से मनाया जाता है। वसंतोत्सव मनाने की परंपरा कालिदास के समय से ही चली आ रही है। आज के दिन बहुत से लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। देश के खेतों में सरसों के पीले फूल भी वसंत की गवाही देने लगते हैं। यह ऋतु एक ऐसे स्थान पर खड़ी है, जहां न गरमी ज्यादा है, न शीत ज्यादा, एक समभाव है। इस सुंदर समभाव पर आप मुग्ध हो जाते हैं। वसंत की जो स्मृति हमारे मन पर बनती है, वह बहुत गहरी होती है और इसी कारण से सबसे ज्यादा वसंत पर ही लिखा गया है। संभव है, कल शायद कभी जलवायु परिवर्तन की वजह से वसंत पहले जैसा नहीं रहेगा, पर उसे तब भी याद रखा जाएगा। यह ऋतु ही अपने आप में अनुष्ठान है, हममें से कोई भूल भी जाए, तो प्रकृति इस अनुष्ठान को मनाने के तमाम यत्न स्वतः करने लगती है। ऐसे में, यह ऋतु हमें सहज सौंदर्य का बोध कराती है। इस ऋतु में भारतीय गांवों-खेतों का सौंदर्य निखर उठता है। यहां कवि पंत जी भी याद आते हैं, *चंचल पग दीप-शिखा-से धर/ गृह, मग, वन में आया वसंत! / सुलगा फाल्गुन का सूनापन/ सौन्दर्य-शिखाओं में अनंत!*

अनेक जगह परंपरा रही है कि वसंत पंचमी के दिन हम वृक्षों, वनस्पतियों के बीच भी जाएंगे, कुछ बजाएंगे, कुछ गाएंगे, अपनी सुंदर प्रकृति को भी सुनाएंगे। जब हम वसंत को महसूस करते हैं, तो मन स्वयं नृत्य करने को मचल उठता है, कुछ गाने को जी करने लगता है। इतनी चीजों के साथ यह जो वसंत का इतना जुड़ना है, उसकी कोई तुलना नहीं है। आज के दिन अपने आसपास जरूर देखना चाहिए। देखिए, अपनी दिल्ली कितनी प्रदूषित हो गई है, अपने हिस्से के वसंत या अपने हिस्से की तितलियों से हाथ धोने लगी है।

फिर भी यह देश संभावनाओं से भरपूर है। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं, एक से बढ़कर एक सुंदर स्थान हैं, अरुणाचल प्रदेश तो विशेष है, जहां साल भर वसंत ठहरा सा लगता है। हमें सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि वसंत हमारे आसपास ही डेरा डाल रह जाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सर्वप्रिय देवी सरस्वती

वैष्णवी मूर्तियों में सरस्वती विद्या की देवी कही जाती हैं। उन्हीं को वाग्देवी, वागीश्वरी, भारती और वाणी भी कहते हैं। सभी देवियों में सरस्वती की मान्यता अधिक है तथा वह सर्वप्रिय भी हैं। विष्णु का लक्ष्मी से, शिव का पार्वती से जो संबंध है, वही ब्रह्मा का सरस्वती से। त्रिदेवों को तीन शक्तियों से संबंधित कर दिया गया। पुराणों में ऐसा ही वर्णन पाया जाता है। परंतु मध्य युग की कला में सरस्वती का संबंध विष्णु से भी दिखलाया गया है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता। पूर्व मध्यकाल में कसौटी प्रस्तर की एक चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा मिली है, जिसकी बायीं ओर वीणा धारण किए सरस्वती की मूर्ति है, दाहिनी ओर लक्ष्मी हैं। दोनों को यथोचित स्थान दिया गया है। पौराणिक विवेचन के पश्चात भी विष्णु के साथ सरस्वती की प्रतिमा आश्चर्यजनक प्रकट होती है।

संभवतः मध्ययुगीन कला में एक विशेषता आ गई, जिसका कारण ब्रह्मा की अप्रधानता है। त्रिदेवों में शिव तथा विष्णु की ही पूजा प्रचलित रही है। लोगों ने ब्रह्मा को भुला दिया, जिसके कारण देवता की पूजा तो शिथिल पड़ गई, परंतु उनकी भार्या सरस्वती की विशेषता बढ़ती गई।... इससे यह नहीं समझना चाहिए कि हिंदू प्रतिमाओं में ब्रह्मा के साथ सरस्वती का अभाव है। मथुरा में ब्रह्मा और सरस्वती की मूर्ति मिली है, जो मध्यकालीन (दसवीं सदी की) समझी जाती है। जैसा कहा गया है, इसका प्रचार क्रमशः जाता रहा, इस कारण केवल सरस्वती की मूर्तियां बंगाल व राजपूताना से मिली हैं। सुंदरवन, बंगाल से 11वीं सदी की एक सुंदर सरस्वती प्रतिमा मिली है, जो आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता (अब कोलकाता) में सुरक्षित है। ऐसी अनेक मूर्तियां जगह-जगह से मिली हैं, जो सरस्वती के सर्वप्रिय होने का परिचय देती हैं।

बौद्ध कला में भी शक्ति के तीन स्वरूप पाए जाते हैं। प्रथम बोधिसत्व के समकक्ष, द्वितीय शक्ति के वेश में तथा तृतीय डाकिनी रूप में। तांत्रिक प्रभाव के कारण जितनी शक्तियां बौद्ध कला में समाविष्ट की गईं, उनमें तारा का विशेष स्थान है। ह्वेनसांग के कथनानुसार तारा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती थी।... यहां इस देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन अप्रासंगिक है; इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि स्वेत तारा की सरस्वती से समता की जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक हिंदू देवियों की तरह सरस्वती को भी बौद्ध धर्म (महायान) में अपनाया गया, जिनको जांगुली तारा कहते हैं।

हिंदू धर्म में सरस्वती को सफेद हंस पर सवारी करते दिखलाते हैं, उनके कारण मनुष्य की बुद्धि निर्मल हो जाती है। इस भावना को बौद्धों ने तारा में आरोपित किया और उनका नाम जांगुली रखा।

हिंदू धर्म में सरस्वती को सफेद हंस पर सवारी करते दिखलाते हैं, यानी सरस्वती के कारण मनुष्य की बुद्धि निर्मल हो जाती है। इस भावना को बौद्धों ने तारा में आरोपित किया और उनका नाम जांगुली रखा। जांगुली के चार हाथ दिखलाए जाते हैं, जो वीणा लिए हुए हैं।

वासुदेव उपाध्याय

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

विश्व में चाहे जहां भी आप जाएं, अपने संस्थान और अपनी जड़ों से सदा जुड़े रहें। आपका यह जुड़ाव और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, साथ ही जीवन को सार्थक बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा।

दोस्ती की नई परिभाषा गढ़ता वैलेंटाइन

आज वैलेंटाइन डे है। यह दिन दोस्ती की परिभाषा की व्याख्या करता है। सभी लोगों को दोस्ती का महत्व बताता है। सिर्फ प्रेमी-प्रेमिका को दोस्त समझने वाले लोगों को बता दूं कि दोस्त शब्द बहुत ही पवित्र होता है। यह बहुत सम्मानित शब्द है। यहां तक कि मां-बाप भी आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बशर्ते आप उनसे दोस्ती करें। भाई-बहन का रिश्ता भी दोस्ती का हो सकता है। दोस्त बनाएंगे, तो देखेंगे कि सामने वाला खुलकर आपसे बात कर रहा है। अपने सुख-दुख आपसे साझा कर रहा है। आप पर पूरा भरोसा कर रहा है। तब आपको एहसास होगा कि आप किस पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं। उन लोगों की तरह दोहरी मानसिकता कतई मत रखिए, जो सार्वजनिक तौर पर तो माता-बहन कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे उनको अलग नजरों से देखेंगे। तमाम तरह की टीका-टिप्पणी करेंगे। मेरा तो यह भी मानना है कि अपने बच्चों को भी दोस्त बना लेना चाहिए। उनसे खुलकर प्यार भरी बातें कीजिए। कुछ कुंठित लोगों की तरह वैलेंटाइन डे के नाम पर दहशत मत पैदा कीजिए। यह सबके साथ मिलकर मनाने वाला दिवस है। इसे सिर्फ प्रेमी-प्रेमिका तक सीमित नहीं कीजिए, बल्कि अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल करिए।

सुनील पटेल, टिप्पणीकार

जरूर मनाएं यह दिन

वैलेंटाइन डे जरूर मनाया जाना चाहिए। यह प्रेम का प्रतीक-दिवस है और हम प्यार में यकीन रखने वाले लोग हैं। हालांकि, इस दिन कुछ लोग बेवजह का तमाशा भी करते हैं। वे पार्कों या बगीचों में बैठे जोड़ों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग असलियत में रूढ़िवादी, पाखंडी व छद्म नैतिकतावादी होते हैं। उनके कृत्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनसे लोहा लेने और उनका सांप्रदायिक विषदंत तोड़ने के लिए यह दिवस व्यापक तौर पर मनाया जाना चाहिए। आरोप लगाया जाता है कि प्रेमी जोड़े अनैतिक काम करते हैं। क्या यह सही आरोप है? अनैतिक तो वे हैं, जो जमाखोरी करते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक ताने-बाने को चोट पहुंचाते हैं। प्रेम में यकीन रखने वाले लोग भला कैसे अनैतिक हो सकते हैं? फिर भी, यदि धर्म के कथित ठेकेदारों से आपको डर लग रहा हो, तो सुरक्षा के कुछ उपाय जरूर अपना सकते हैं। जैसे, लड़कियां अपने पास लाल मिर्च का पाउडर रख सकती हैं, ताकि इन कथित नैतिकतावादियों की आंखें जलाई जा सकें। इसी तरह, लड़के भी इनका डटकर मुकाबला करें। वास्तव में, वैलेंटाइन डे के विरोधी कुंठित, निराश और अनाड़ी होते हैं, उनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं।

प्रभात कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

वैलेंटाइन डे

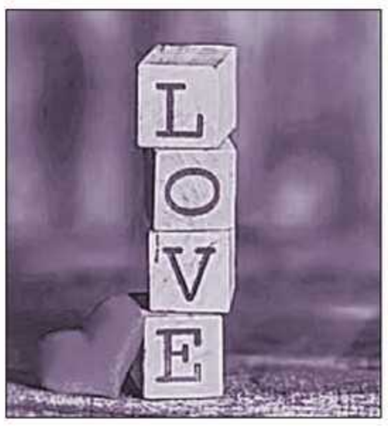

पवित्र प्रेम को बदनाम करने वाला दिन

रोने से और इश्क में बेबाक हो गए/ धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। प्रेम एक दैवीय गुण है। अपूर्णता में पूर्णता का भाव है। प्रेम ही इस लोक में शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। भारत की संस्कृति प्रेममय रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वसंत पंचमी का पावन पर्व है। इसे वसंतोत्सव और मदनोत्सव भी कहा जाता है। प्राचीन काल में स्त्रियां इस दिन अपने पति (ध्यान रखें पति) की कामदेव के रूप में पूजा करती थीं, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन कामदेव और रति ने सर्वप्रथम मानव हृदय में प्रेम व आकर्षण का संचार किया था। यही प्रेम व आकर्षण दोनों के अटूट संबंध का आधार बना। लिहाजा, प्रेम का कोई विशेष दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो हर दिन, हर घड़ी, हर पल किया जा सकता है। पश्चिमी देशों, विशेषकर इटली में, जहां से यह दिवस आयातित हुआ है, वहां भी अब यह महज प्रेमी-प्रेमिका या शादीशुदा जोड़े तक नहीं, बल्कि घर के सभी सदस्यों के लिए एक-दूसरे के प्रति प्यार दर्शाने का दिवस बन गया है।

सच यही है कि अब मोहब्बत एक तिजारत हो गई है। प्रेम का बाजारीकरण हो गया है। माना यह भी जाता है कि जिस तरह करवा चौथ *दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे* फिल्म का बाय-प्रोडक्ट है, उसी तरह वैलेंटाइन डे यश चोपड़ा की फिल्म *दिल तो पागल है* की देन है। भावनाओं के बजाय यदि हम आंकड़ों की बात करें, तो पिछले तीन वर्ष में भारत में 40 लाख से अधिक लड़कियों में बांझपन और 30 लाख में कैंसर पाया गया। मैं यह नहीं कहती कि यह सब वैलेंटाइन डे की देन है, लेकिन खबरें यह भी बताती हैं कि इस तथाकथित दिवस के बाद बमुश्किल 10 दिनों के अंदर गाइनेकोलॉजिस्ट के पास भीड़ बढ़ जाती है।

सरकार हर साल मातृत्व सुरक्षा, जननी सुरक्षा, बेटी बचाओ जैसी योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है, लेकिन आज हालत यह है कि कम उम्र की लड़कियां भी अपने पर्स या बैग में अपनी मौत का सामान लेकर घूमती दिख जाती हैं। ऐसी जहरीली और भ्रामक चीजों को जान-बूझकर वैलेंटाइन डे के आसपास प्रचारित किया जाता है, ताकि बाजार अपना फायदा कमा सके। उसकी इस कमाई का कुछ हिस्सा निश्चय ही नौकरशाहों और राजनेताओं तक भी पहुंचता होगा। लिहाजा, वैलेंटाइन डे जैसे दिवसों को बढ़ावा देने वाली मानसिकता को हमें रोकना होगा। आज बाजारीकरण के काले सच को समझने और युवा पीढ़ी को इस मृग-मरीचिका से बचाने की जरूरत है।

आशा विनय सिंह बैस, टिप्पणीकार

मुस्लिम वोट पर सबकी निगाह

जब चुनावी मौसम आ पहुंचा है, तब यह चर्चा गली-गली में तेज होने लगी है कि इस बार कौन किसको क्यों वोट देगा। ध्यान रहे, देश में कम से कम 101 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम मतदाता हार-जीत में कारगर हो सकते हैं, पर क्या वे एकमुश्त वोट करते हैं? अभी तक चुनावों में उन्होंने क्या किया है? पेश है हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े वरिष्ठ शोधकर्ता फैयाद अली की खास रिपोर्ट ...

लोकसभा चुनाव 2019 में किसके पक्ष में हुआ मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण

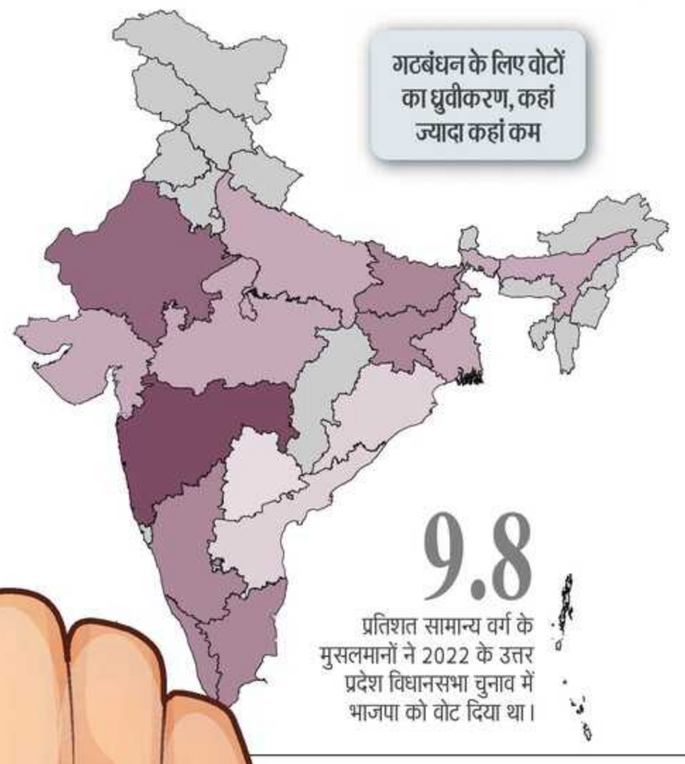

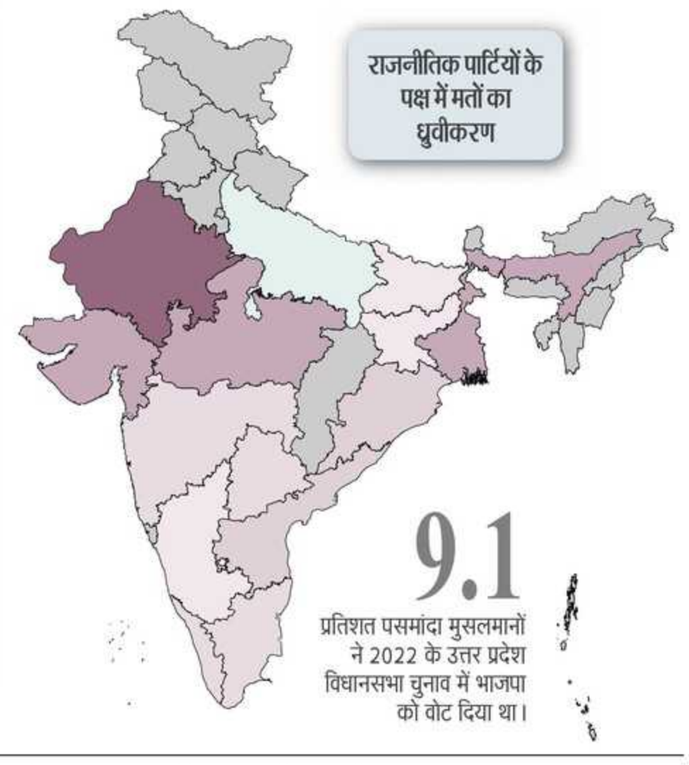

कहीं मुस्लिम वोटों का रुझान किसी पार्टी के प्रति ज्यादा है, तो कहीं किसी गठबंधन के प्रति। सभी आंकड़े शोधकर्ता हिलाल अहमद और अदनान फारूकी के अलग-अलग अध्ययन-शोध रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन अध्ययनों में राजनीति में अल्पसंख्यकों की भागीदारी की खबर ली गई है। नक्शे में स्लेटी रंग में ऐसे राज्य हैं, जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

एच एच इंडेक्स पर स्कोर : जहां रंग गाढ़ा, वहां ज्यादा मुस्लिम ध्रुवीकरण

.25 .5 .75

मुस्लिम मतदाताओं का कम ध्रुवीकरण — मुस्लिम मतदाताओं का ज्यादा ध्रुवीकरण

साल 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद से शोधकर्ताओं ने मुस्लिमों के मत का करीब से अध्ययन किया है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि बाद के राज्य विधानसभा चुनावों में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ उन पार्टियों के पक्ष में मतदान किया है, जो भाजपा को चुनौती दे सकती हैं। हालांकि, इस अध्ययन के अनेक पहलू हैं। मुस्लिम वोटों के इस ध्रुवीकरण के साथ-साथ, मुस्लिम आबादी के बीच अनेक सामाजिक व राजनीतिक भेद एक साथ सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, मुस्लिम समाज में मौजूद विभिन्न जातियां अब मुख्यधारा की राजनीतिक चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बन गई हैं। इस समाज के लोग किसको वोट देंगे, यह सवाल आगामी चुनाव के मद्देनजर गंभीर बनता जा रहा है। क्या एकमुश्त मुस्लिम वोट के विचार को खारिज कर देना चाहिए? मुस्लिम मतदाताओं के व्यवहार को समझने के लिए जाति किस हद तक प्रासंगिक है? क्या इस समुदाय के

अभी जो राजनीतिक परिवेश है, उसमें 2019 के आम चुनावों के बाद से मुसलमानों के एकजुट होकर मतदान करने की संभावना अधिक हो गई है, पर साथ ही, मुस्लिम समुदाय में जाति या जातियों का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है। भाजपा द्वारा पसमांदा मुसलमानों की लामबंदी जोर पकड़ने और विपक्षी दलों द्वारा जवाबी कार्रवाई की कोशिश के साथ, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए जाति के नजरिए को सिर्फ हिंदू समुदाय तक सीमित रखना नासमझी होगी। अभी घोषित रूप से मुस्लिमों के पक्षधर राजनीतिक दल भी अपने पक्ष में मतदान को लेकर आश्वस्त नहीं हैं।

बीच मजहब और जाति-उपजाति के बावजूद समूह-आधारित एकजुटता कायम है?

गौर करने की बात है कि लोकप्रिय चुनाव विश्लेषणों में मुसलमानों को अक्सर एक सजातीय मतदान समूह के रूप में मान लिया जाता है। हालांकि, मुसलमान शायद ही कभी मिलकर एक अटूट मतदाता समूह बनाते हैं। वास्तव में, हिंदुओं की तरह ही मुसलमान भी अनेक वर्ग, फिरके, जाति और क्षेत्रीय आधार पर बंटे हुए हैं।

वैसे 2019 से पहले भी मुस्लिम मतदान काफी हद तक बंटा हुआ था, पहले भी किसी एक राजनीतिक दल के पीछे साफ तौर पर चले जाने के संकेत नहीं थे, पर खासकर भाजपा की 2019 की जीत के बाद से मुस्लिम मतदान का विषय ज्यादा जटिल हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ आम तौर पर वोटों के बंटवारे को ठीक से जांचने के लिए हेरफिंडाहल-हिर्शमैन इंडेक्स (एचएचआई) नामक एक माध्यम का उपयोग करते हैं। इस सूचकांक पर शून्य के करीब स्कोर का मतलब है कि सभी मुसलमानों ने अलग-अलग पार्टियों को वोट दिए हैं, जबकि 1 का स्कोर एक ही पार्टी को दिए गए समर्थन को दर्शाता है। 2019 के आम चुनावों में बढ़े हिंदू बहुसंख्यकवाद के बावजूद मुस्लिम वोटों के कुछ बंटने का पता चलता है। इसके अलावा, राज्यों के बीच भी काफी भिन्नता है। पार्टियों और गठबंधनों के हिसाब से भी मुस्लिम वोटों का बंटवारा जगजाहिर है।

तुलनात्मक रूप से 2019 के आम चुनावों के बाद से राज्य विधानसभा चुनावों में मुस्लिम मतदान का अध्ययन रोचक है। सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 77 प्रतिशत मुसलमानों ने महागठबंधन (भाजपा के विरोध में बने गठबंधन) को वोट दिया था। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 75 प्रतिशत मुसलमानों ने मौजूदा तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 79 प्रतिशत मुसलमानों ने विपक्षी समाजवादी पार्टी को वोट दिया था।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि मुसलमान किसी राज्य के चुनावी स्थिति या व्यक्तिगत उम्मीदवार की संभावनाओं के मुताबिक वोट करते हैं। मुस्लिम वोट बहुध्रुवीय मुकाबलों में बंट जाते हैं। राज्य विधानसभा चुनावों पर केंद्रित मेरा अपना एक अध्ययन बताता है कि मुस्लिम मतदाता का व्यवहार एक स्वधर्मी या स्वजातीय प्रतिनिधि की मौजूदगी या नामौजूदगी से प्रभावित होता है। किसी मुस्लिम उम्मीदवार की मौजूदगी भी मुसलमानों के बीच वोटों के बंटवारे की एक वजह बन सकती है। वोटों का यह बंटवारा वास्तव में समग्र मुस्लिम पहचान के अंदर उप-पहचानों से प्रभावित होता है।

मजहब के भीतर जाति

अनेक जानकार इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं, पर मुस्लिम समुदाय में भी जातियां एक प्रासंगिक उप-पहचान बनी हुई हैं। मुस्लिम समुदाय की पहचान को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: अशराफ, अजलाफ और अरजाल। अशराफ मुस्लिम आप्रवासियों के स्वयंभू वंशज हैं, जो यह मानते हैं कि वे मध्य-पूर्व और मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे; इस समूह में सैय्यद, शेख, मुगल और पठान शामिल हैं। अजलाफ और अरजाल मुख्य रूप से ऐसे मुस्लिमों के समूह हैं, जो पहले हिंदू थे। उन्होंने अपने नए मजहब को मंजूर किया, पर अपनी पुरानी जाति को साथ ले गए। इन समूहों में हिन्दुओं की तरह ही अनेक जातियों का प्रभाव है। 1990 के दशक से, गैर-अशराफ मुसलमानों - अजलाफ (ओबीसी) और अरजाल (दलित) मुसलमानों - के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यधारा राजनीति में अशराफ के प्रभुत्व के खिलाफ लामबंद होने की अपील की है। ये समूह खुद को सामूहिक रूप से पसमांदा (एक फारसी शब्द - जिसका अर्थ है - पीछे छोड़ दिए गए) के रूप में पेश करते हैं। आज पसमांदा मुस्लिम शब्द का उपयोग ओबीसी और दलित मुसलमानों के लिए किया जाने लगा है।

2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट को अक्सर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच शैक्षिक और आर्थिक अंतर को उजागर करने के लिए उद्धृत किया जाता है, लेकिन यह मुस्लिम आबादी के भीतर, खास तौर पर जाति के आधार पर भेद या दूरियों की भी जांच करती है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में मतदान प्रतिशत

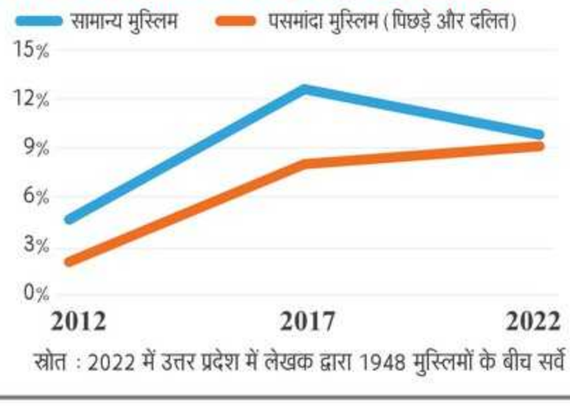

स्रोत : 2022 में उत्तर प्रदेश में लेखक द्वारा 1948 मुस्लिमों के बीच सर्वे

सामान्य मुस्लिम और पसमांदा के बीच रुझान

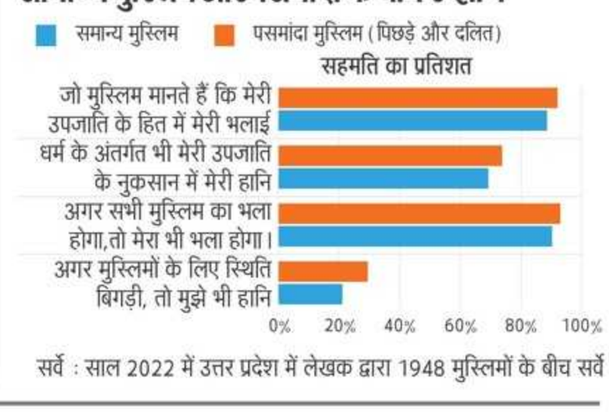

सर्वे : साल 2022 में उत्तर प्रदेश में लेखक द्वारा 1948 मुस्लिमों के बीच सर्वे

पहचान का राजनीतिकरण बढ़ रहा है। मुसलमानों के सामाजिक-आर्थिक जीवन के लिए प्रासंगिक होने के अलावा जाति उनके बीच भी तेजी से राजनीति और चर्चा का हिस्सा बन रही है। नागरिक जीवन के संदर्भ में, मुस्लिम जाति-आधारित लामबंदी के सुबूत बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, पसमांदा आंदोलन के केंद्र में एक संगठित ताकत बिहार में मौजूद अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम महाज (एआईपीएमएम) है। एआईपीएमएम दलित मुसलमानों (साथ ही दलित ईसाइयों) को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने, उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षा और राजनीति में सकारात्मक कार्रवाई और अत्याचारों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की वकालत करने के नागरिक प्रयासों में सबसे आगे रहा है। पिछले कई वर्षों में राजनीतिक अभिजात वर्ग ने भी मुसलमानों को जाति के आधार पर लामबंद करने के प्रयासों का विस्तार किया है। इस लामबंदी का अधिकांश हिस्सा पसमांदा समूह पर आधारित है, बिहार में अंसारी उपजाति की लामबंदी के भी कुछ सबूत हैं।

साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने पसमांदा मुसलमानों पर ज्यादा ध्यान दिया, भाजपा कार्यकर्ताओं से पसमांदा मुसलमानों तक पहुंचने का आग्रह किया गया। प्रधानमंत्री ने वर्ष के अंत में रसूखदार पसमांदा मुसलमानों के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए। वैसे भाजपा ने पहले भी पसमांदा मुसलमानों के लिए काम किए हैं। मिसाल के लिए, समाजशास्त्री खालिद अनीस अंसारी ने कहा कि 2013 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कुछ पसमांदा मुसलमानों को शामिल करने के लिए एक बुनकर सेल गठित किया था और 2017 में ओडिशा में पार्टी ने पसमांदा मुसलमानों को ओबीसी के समान लाभ देने की जरूरत पर प्रकाश डाला था।

बहरहाल, भाजपा पसमांदा मुस्लिमों तक पहुंची जरूर, पर उसे कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। वैसे कई मुस्लिम समूहों ने पसमांदा समुदाय के लोगों को भाजपा से सावधान रहने की भी सलाह दी है। उदाहरण के लिए, एआईपीएमएम ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल को पसमांदा मुसलमानों के समर्थन को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो नियमित रूप से मुस्लिम एकजुटता का आह्वान करते हैं, ने भी भाजपा की आलोचना की है और तर्क दिया है कि पसमांदा मुसलमान भाजपा सरकार के रहते हुए भी अनेक बार हिंसा के शिकार हुए हैं।

वैसे आरोपों से परे जमीनी हालात को समझना होगा। इसी दिशा में मैंने 2022 में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच एक सर्वे किया था। 2012 में उत्तर प्रदेश में राज्य चुनावों के बारे में पूछे जाने पर मुस्लिम मतदाताओं के एक छोटे प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया था। साल 2017 तक 12.6 प्रतिशत सामान्य मुसलमानों और 8 प्रतिशत पसमांदा मुसलमानों ने भाजपा का समर्थन करने की सूचना दी। दिलचस्प है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों तक सामान्य मुसलमानों के बीच भाजपा का समर्थन गिरकर 9.8 प्रतिशत हो गया, जबकि पसमांदा मुसलमानों के बीच समर्थन बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गया।

आगामी चुनाव में भाजपा के लिए पसमांदा समर्थन में बढ़त संभव है, पर अगर हिन्दू वोट के लिए भाजपा ने ज्यादा प्रयास किए, तो जाति की परवाह किए बिना मुसलमानों के लिए भाजपा को वोट देना मुश्किल हो सकता है। वैसे शक नहीं कि मुसलमान अपना व्यापक हित देखने लगे हैं।

यदि भाजपा पसमांदा मुसलमानों तक अपनी पहुंच बनाने में मामूली रूप से भी कामयाब रहती है, तो चुनावी पंडितों को एकमुश्त मुस्लिम मतदान के विचार को रिटायर करना पड़ेगा। अब यह जरूरी हो गया है कि मुस्लिमों के बीच भी उप-जातियों या उप-पहचानों के प्रभाव का आकलन किया जाए। कौन किधर मतदान कर रहा है, इसे सूक्ष्म स्तर पर देखना-समझना होगा।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। मन अशांत रहेगा। बेकार की बहस में न पड़ें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

वृष : मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी। कारोबार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। माता-पिता का साथ मिलेगा।

मिथुन : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में कार्यभार में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क : मन में उतार-चढ़ाव रहेगा। आत्मसंयत रहें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

सिंह : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मीठे खानपान में रुचि। सेहत पर ध्यान दें।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

तुला : मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ में भी वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। वाहन सुख में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : मानसिक शांति रहेगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिलेंगे। कार्यभार में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

धनु : पठन-पाठन में रुचि रहेगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा। विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। किसी मित्र के सहयोग से आयवृद्धि।

मकर : मन अशांत हो सकता है। संयत रहें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। भवन सुख में वृद्धि होगी। माता-पिता का सान्निध्य।

कुंभ : आत्मविश्वास रहेगा। परंतु अपनी भावनाओं को वश में रखें। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। किसी मित्र से धन मिल सकता है।

मीन : मन प्रसन्न रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। सेहत का ध्यान रखें।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

14 फरवरी, बुधवार, 25 माघ (सौर) शक संवत् 1945, 02, फाल्गुन मास प्रविष्टे (पंजाब पंचांग) 2080, 03, शब्बान सन् 1445, माघ शुक्ल पंचमी (विक्रमी संवत्) दोपहर 12.10 मिनट तक। शुक्ल योग, बालव करण। चंद्रमा मीन राशि में प्रातः 10.43 मिनट तक उपरांत मेष राशि में।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। पंचक समाप्त प्रातः 10.43 मिनट तक। वसंत पंचमी। लक्ष्मी/सरस्वती पूजन। गंडमूल विचार।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

आवास के लिए भूमि का चयन किस प्रकार करना चाहिए? -रंजना, पटना

- जहां तक संभव हो आवास के लिए 'जीवित भूखंड' ही खरीदना चाहिए, अर्थात जिस भूखंड पर हरे-भरे वृक्ष उग रहे हों, अन्नादि की उपज भी उत्तम हो, उसे ही जीवित भूखंड समझना चाहिए।
- जिस प्रकार सात्विक भोजन शरीर के साथ ही मन को भी प्रसन्न कर देता है, ठीक उसी प्रकार शुभ एवं आनन्द देने वाली भूमि मन को भी शीतलता देती है, और उस पर आवास बना कर रहने पर पूरा जीवन आनन्द में ही व्यतीत होता है।
- उसके आस पास कोई बड़ा बिजली का टावर, धार्मिक स्थान या टी पॉइंट न हो।

वर्ग पहेली : 7513

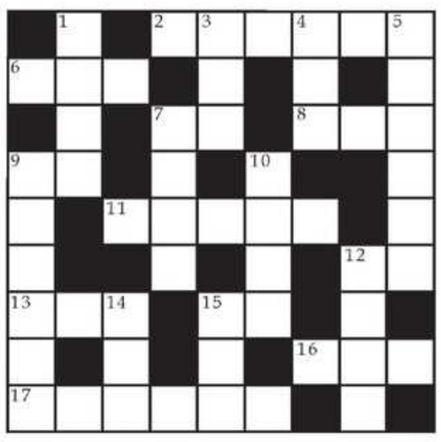

बाएं से दाएं
2. वस्तु; सामान; संपत्ति (2,4)
6. बदकिस्मत; बदबख्त; भाग्यहीन (3)
7. इज्जत; कीर्ति; ख्याति; धाक; प्रतिष्ठा; संज्ञावाचक शब्द (2)
8. जिसका नाम लिखा गया हो; नामांकित (3)
9. ईश्वर भक्त; महात्मा; संन्यासी; साधु (2)
11. जिसके घटित होने की कोई संभावना न हो; जिसके होने का अनुमान न किया गया हो (5)
12. अनुभव करना; जान लेना; खोज निकालना; ढूंढ़ निकालना; प्राप्त करना; मिलना (2)
13. आकर्षक; कलापूर्ण; मुग्ध करने वाला; मोहित करने वाला; सुंदर (3)
15. आठ पहर का समय; दिवस; यौम; वार (2)
16. रंग चढ़ाना; रंग लगाना; रंग में डुबाना; प्रेम में फंसाना (3)
17. नरक में जाना; नरक में रहना (3,3)

ऊपर से नीचे
1. जिसे लाभ प्राप्त हुआ हो; लाभ पाने वाला; लाभार्थी (4)
3. रास; बागडोर (3)
4. भरना; लीन होना; समा जाना (3)
5. बचाना; लाभ कमाना (3,3)
7. जिसे जी न चाहे; अप्रिय; अरुचिकर (4)
9. कष्ट से छुटकारा दिलाने वाला; संकट से मुक्त करने वाला; त्राणदाता; हनुमान (6)
10. विधान या कानून जिसके अनुसार आसन संचालन होता है; व्यवस्था; रचना (4)
12. जो पार हो चुका हो; पूर्ण पंडित; ज्ञानी (4)
14. टीस; साल; अभिलाषा; अरमान (3)
15. अभिमान; बुद्धि; मस्तिष्क; समझ; भेजा (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली

(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 7512 का उत्तर

सुडोकू : 7497 * कठिन

	9				7	4		
1						8		
		4		6	9			
8				4			1	2
9	4			5				6
			7	8		1		
		1						5
		6	5				8	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 7496

6	8	5	9	1	7	4	2	3
9	4	1	6	2	3	7	8	5
3	2	7	8	5	4	6	1	9
1	5	3	4	9	2	8	6	7
4	6	8	5	7	1	9	3	2
7	9	2	3	6	8	5	4	1
5	3	6	1	4	9	2	7	8
8	7	4	2	3	5	1	9	6
2	1	9	7	8	6	3	5	4